MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

Internal security situation in the country

श्री उपसभापति: श्री अबू आसिम आज़मी।

†**श्री अबू आसिम आज़मी** (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन, सर। ''इन्टरनल सिक्यूरिटी सिच्युएशन इन ऑवर कन्ट्री'', मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद पेश करता हूं। देश में तीन तरह के मेजर प्रॉब्लम हैं, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम है–आरगेनाइज्ड क्राइम, टेरोरिज्म और कम्युनल फोर्सेज़। यह देखा गया है कि सरकार ने देश में आरगेनाइज्ड क्राइम के लिए और टेरोरिज्म के लिए, उसको रोकने के लिए, स्पेशल कानून बनाए–मीसा, एनएसए, टाडा और पोटा। स्पेशल फोर्सेज़ बनाई गई। लेकिन कम्युनल फोर्सेज़ को रोकने के लिए, इन एलीमेंट्स को रोकने के लिए, सरकार ने कोई स्पेशल फोर्स, कोई स्पेशल कानून इसके लिए नहीं बनाया। हमारे देश के अन्दर पिछले 57 सालों में, 1947 से लेकर आज तक इस देश में तकरीबन 13 हजार कम्युनल रायट्स हो चुके हैं। अब इसे यह कह कर कि यह रॉयट है, मुंह चुरा लेने से या फिर रॉयट बोल देने से बात नहीं बनती। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि यह सिर्फ कम्युनल रॉयट नहीं, यह बिल्कुल टेरोरिज्म है और आज अगर देश में इन्टरनल सिक्युरिटी का इस देश में मसला हो गया है तो सबसे बड़ा मसला कम्युनल फोर्सेज का है, जो इस देश में रहने वाले लोगों को दो तरह से देखते हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि आज देश की दुश्मन फोर्सेज़ हमारे देश के अन्दर कहीं–न–कहीं टेरोरिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहीं हैं। इसके लिए फोर्सेज़ बार्डर पर बड़ी मेहनत से लड़ रही हैं, बड़ी सख्ती के साथ लड़ रही हैं। परन्तु देश के अन्दर रहने वाले वे लोग जो आज जाति के नाम पर, मन्दिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहें हैं,

---

†Transliteration of Urdu Script.

इससे देश के अन्दर इन्टरनल सिक्युरिटी का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। 1992-93 के दंगों को अगर देखा जाए, गुजरात के फसाद पर अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छी तरह से यह बात समझ में आएगी। मगर अफसोस, कि जो लोग दंगों के जिम्मेदार थे, वे हुक्मरान बन गए, बड़े-बड़े मंत्री बन गए, बड़े-बड़े पदों पर बैठ गए और उनके दिमाग में एक बात आ गई कि दंगा कराओ और हुकुमत करो। अगर पिछले ज़माने को याद किया जाए, हिस्ट्री को याद किया जाए तो जब अंग्रेजों की सरकार थी, अमृतसर के अन्दर जब जालियाँवाला बाग का वाकया हुआ था। क्या था वह? सरकार थी अंग्रेजो की, वे गुलामों की तरह से भारतवासियों के साथ पेश आते थे, गुलाम बना कर रखा हुआ था। एक कानून के खिलाफ जालियाँवाला बाग में भारतवर्ष के बीस हजार लोग एक आन्दोलन कर रहे थे। जनरल डायर ने वहां गोलियां चलाकर दो हजार से तीन हजार लोगों को मार डाला। एक 14-15 साल की उम्र का छोटा सा बच्चा, जो लाशों के अम्बार में दबा हुआ था जब उसे देखा कि किस तरह से जुल्म और ज्यादती हुई, तो उसने यह कसम खायी कि मेरी जिन्दगी का मकसद यह होगा कि जब तक मैं जनरल डायर से बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूगां। जनरल डायर को यहां से लन्दन बुला कर वहां उसका स्वागत किया जा रहा था, उसका फेलिसिटेशन किया जा रहा था कि जनरल डायर ने दो से तीन हजार हिन्दुस्तानियों को मारा। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए, सिर्फ बदला लेने के लिए, उस भरी सभा के अन्दर, उसे गोली मार दी। ऊधम सिंह को आज हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं अपने देश का, बहुत झुक कर उसकी अज़मत को सलाम करते हैं और इस देश का स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि 1992-93 में जो दंगे हुए और श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई, उसके बाद बम्बई में बम ब्लास्ट हो गए। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर लिखा हुआ है कि बाम्बे ब्लास्ट में जिन लोगों का इन्वाल्वमेंट है, वे 1992-93 के राइट के विक्टिम थे। कहीं-न-कहीं अगर हम संज़ीदगी से इस पर ध्यान दें तो यह होता है जुल्म और ज्यादती की वजह से बहुत सारे लोग टेरोरिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगर आप गुजरात की फसादात की तरफ ध्यान दें, तो शर्म से हमारी गर्दन झुक जाती है, सारी दुनिया में हमारे देश की थू-थू हुई। आज बिलकिस बानों और बेस्ट बेकरी के केसेज हुए जिन में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये मुकदमे गुजरात में नहीं चला सकते, इसे दूसरी स्टेट में ले जाओ। वह मुकदमा दूसरे स्टेट में चलाया जा रहा है। उन को इंसाफ नहीं मिला है। गुजरात के अंदर गांवों में घुसकर लोगों ने वे औरतें जो अपने पति और बच्चों के साथ सोयी हुई थीं, उन्हें वहीं नंगा करके बलात्कार किया। उस के बाद औरत पुलिस स्टेशन में जाकर कम्प्लेंट करती है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, किसी को सजा नहीं होती। तो जब वह नौजवान अपनी मां को, अपनी बहन को रेप होते हुए देखेगा तो उस के दिल में नफरत ज्वालामुखी की तरह उठेगी और ऐसे समय में जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जो हमारे मुल्क में बद-अमनी फैलाना चाहते हैं, वे लोग उसे शह देकर कहीं-न-कहीं से उसके साथ कांटैक्ट में आकर, हमारे देश के अंदर हमारी इंटरनल सेक्युरिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): महोदय, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो बातें कह रहे हैं या तो सब्स्टेंसिएट करें और अगर सब्स्टेंसिएट नहीं कर सकते तो सदन के माध्यम से पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश न करें।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** कैसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो इंटरनल सेक्युरिटी की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी इंटरनल सेक्युरिटी खराब हो रही है। ...**(व्यवधान)**... देश की इंटरनल सेक्युरिटी की बर्बादी उन्हीं नफरत फैलाने वालों की वजह से हो रही है। ...**(व्यवधान)**... फिर आप बोलना शुरू कर देते हो। ...**(व्यवधान)**... ये वही* दल के लोग थे जो देश में नफरत फैला रहे हैं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

†**श्री अबू आसिम आजमी:** ये गलत बात है और गलत बात को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ये सदन के माध्यम से पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है।...**(व्यवधान)**...

†**श्री अबु आसिम आजमी:** हम सदन के माध्यम से देश से पूछना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: इसलिए या तो वह इन चीजों को सब्स्टेंसिएट करें या बताएं कि ...**(व्यवधान)**...किस रिपोर्ट में इस का उल्लेख है।

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप 1984 का भी उल्लेख कीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** उस का भी करेंगे।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): सर, यह क्या हो रहा है। वह अपनी मर्जी से बोलेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए, आप बैठिए, आप बैठिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: वह पहले खड़े हुए इसलिए पहले वह बैठेंगे। आप उन्हें बिठाइए।

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, देखिए हर मेंबर के अपने विचार होते हैं। अब वह अपने विचार रख रहे हैं

---

* Expunged as ordered by the Chair.

† Transliteration of Urdu Script.s

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: यह विचार नहीं है, यह आरोप है।

श्री उपसभापति: देखिए, सदन में ऐसे आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं। अब उस के लिए चेयर से डायरेक्शन नहीं दी जाती। अगर वह आरोप कर रहें तो आप का जब मौका आएगा तो आप उस का जवाब दीजिए। चलिए, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

†**श्री अबू आसिम आजमी:** हम वतन के चाहने वाले लोग हैं। हम नफरत फैलाने वालों को उजागर करना चाहते हैं। हम दिलों को मिलाना चाहते हैं। सर, इस देश में इंटरनल सेक्युरिटी के लिए पोटा कानून बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में किसी ने ट्रेन जला दी, आप इंक्वायरी करो और जिस ने भी ट्रेन जलायी, उसे सख्त-से-सख्त सजा दो। उसे ऐसी सजा दो कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं और दोबारा कोई इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश न करे। आप इंक्वायरी करो तो पता चलेगा कि वह काम किसने किया और जिसने भी किया उसे सजा दो। उस में कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन 80 लोग जलाए गए तो 180 लोगों को पोटा में बंद कर दिया गया। फिर एक जिम्मेदार आदमी कहता है कि यह एक्शन का रिएक्शन है और उसके बाद ढाई हजार लोग जला दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... आप बताओ कि पोटा कितने लोगों पर लगाया गया? अगर 80 लोग जलने पर 180 लोगों पर पोटा लगाया गया। गुजरात में 180 लोग पोटा में बंद हैं, उन में 179 मुस्लिम हैं और एक सिख समुदाय का है।

श्री उपसभापति: आजमी साहब, आप कंक्लूड कीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** दूसरी जगह 25 सौ लोग मारे गए और एक को पोटा नहीं लगाया गया।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वही बात बता रहे हैं। आपको पता नहीं है ...**(व्यवधान)**...

†**श्री अबू आसिम आजमी:** मुझे पता है। आपका जब बोलने का टाइम आएगा तो बता दीजिए।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** अभी तो शुरू हुआ है। अभी कैसे कन्क्लूड होगा? सर अभी दो ही मिनट तो हुए हैं। डिप्टी चेयरमैन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस, इकॉनॉमिक इनजस्टिस जब तक इस देश में रहेगा, उस वक्त तक इस देश में इन्टरनल सेक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला रहेगा। आज इस सदन को तय करना पड़ेगा कि इस देश में किस तरह से सोशल इनजस्टिस खत्म हो जाए। क्या इससे बड़ी कोई मिसाल और मिल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजरात में मुकदमा मत चलाओ। व्रहां कोर्ट नही है? वहां पुलिस नही हैं?

†Transliteration of Urdu Script.

वहां हुकूमत नहीं है? मुकदमा चलाने के लिए दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है और ऐसी सरकारें चल रही हैं। ऐसी सरकार को तो उसी दिन उसको खत्म कर देना चाहिए। देश को बरबाद करने वाले जो लोग है, जो इस तरह की चीजें इस देश में चला रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप उनको जवाब मत दीजिए। आप मुझको एड्रेस कीजिए ...(**व्यवधान**)...

†**श्री अबू आसिम आजमी:** देश के अंदर, आज गरीब किसान खुदकुशी कर रहा है, लेकिन अगर किसानों की हालत सुधारी नहीं गयी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कल यही किसान जो मर रहा है? यह किसान लोगों को मारना शुरू करेगा और इस बात को याद रखिए कि जुल्म और नाइन्साफी की कोख से पैदा होता है-आतंकवाद ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** मुझे लगता है कि ''चोर की दाढ़ी में तिनका'' ...(**व्यवधान**)... क्या ये वही लोग हैं?

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** 57 साल से कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वाजपेयी जी ने स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। राजीव गांधी ने वहां हीलिंग टच का नारा दिया। पूरा नहीं हुआ। इन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने उन चीजों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया होता तो हमारे यहां की सेक्योरिटी का मसला हल हो सकता है। दो दिनों पहले के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ था कि यहां तो झूठा एनकाउन्टर हो रहा था। लेकिन अब झूठा सरेन्डर भी हो रहा है। रेप, किडनैपिंग, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर पर पाबंदी लगायी जाय। ...(**व्यवधान**)...

श्री एकनाथ के० ठाकुर (महाराष्ट्र): बम ब्लास्ट पर भी पाबंदी लगायी जाय।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** बिल्कुल, बहुत जरूरी लगायी जाय। बम ब्लास्ट पर भी पाबंदी लगायी जाय और जो लोग बम ब्लास्ट करने वाले हैं, उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाय ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। एकनाथ जी, आप जब बोलेंगे तो बोलिए। उनको बोलने दीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** ह्यूमन राइट संगठन को खुले तौर पर काम करने दिया जाए, यह

†Transliteration of Urdu Script.

सबसे जरूरी है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कहीं कुछ होता है तो कमीशन बिठा दिया जाता है? मगर उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता। उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराया जाय तो मालूम हो जाएगा कि 92-93 की रिपोर्ट को लागू करा दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा था? उस वक्त के मेयर साहब, 92-93 के जो बॉम्बे के मेयर थे वे जाकर बैठे हुए थे शिवसेना के सुप्रीमो के पास और वे सुन रहे थे कि वे टेलीफोन पर क्या-क्या कह रहे हैं। परन्तु मुझे अफसोस है कि आज श्री कृष्ण कमीशन को लागू नहीं किया जा रहा है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप दूसरी पार्टियों को रेफर मत कीजिए। बंद कीजिए ...(व्यवधान)... आप इधर एड्रेस कीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथी इस बात से नाराज न हों लेकिन सच्चाई यह है कि उस वक्त मेयर एक अखबार वाले के साथ वहां बैठे हुए थे, शिवसेना के सुप्रीमो के पास ...(व्यवधान)... जितनी ज्यादा आज बॉर्डर पर फोर्सेज लगी हुई हैं, उसी तरह से इन लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए उतनी ही फोर्सेज देश के अन्दर लगनी चाहिए। अफसोस कि एक कैबिनेट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, बॉम्बे जाता है। सर, इस मुल्क का पेट्रोलियम मिनिस्टर मुम्बई जाता है, वहां इतनी * बढ़ गई है कि वह वहां पर मीटिंग नहीं कर सकता। उसे वापस आना पड़ता है। ...(व्यवधान)... मैं कहता हूं कि कोई दस-बीस हजार * पालकर यह समझे कि हम संविधान को नहीं समझते हैं तो यह देश नहीं चल सकता। यह देश संविधान से चलेगा। यह देश किसी की * से नहीं चलेगा। नफरत को मिटाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अवाम को एतमाद में लेकर के.....

श्री उपसभापति: आपका वक्त खत्म हो गया है। कनक्ल्यूड कीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** बस, मेरा हो गया, सर। यह मेरे दिल का दर्द।

श्री उपसभापति: आजमी साहब, दर्द तो है, मगर वक्त की भी पाबंदी है।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** सर,

जब गुलिस्तां को खूं की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी।

अब ये कहते हैं हमसे यह अहले चमन, यह हमारा चमन है, तुम्हारा चमन नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह क्या कह रहे हैं? शेर बोला तो उस पर भी आप खड़े हो गए? ...(व्यवधान)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.
†Transliteration of Urdu Script.

†**श्री अबू आसिम आजमी:** उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर श्रीकृष्ण कमीशन लागू हो गया होता, अगर 1992-93 के फसादात के जो लोग जिम्मेदार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज देश की हालत ऐसी नहीं हुई होती ...(**व्यवधान**)...

श्री एकनाथ के० ठाकुर: सर। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: देखिए, जब आपका नंबर आए, बोलिएगा। Please sit down. आप अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं, बाहर आकर बोल रहे हैं। अपनी सीट पर बैठिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज बैठिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** इसलिए मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: अब आप कनक्ल्यूड कीजिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** मुझे अफसोस इस बात का है कि आज देश जो है, कम से कम उसमें महाराष्ट्र राज्य जो है, वह संविधान से नहीं चल रहा है। बहुत घबरा गए हैं ये लोग। इसलिए अगर इसे देश की इंटरनल सेक्युरिटी को सही करना है, तो मोहब्बत फैलाना है। मैं कहता हूं कि-

एक सज़र ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए,
जिसका आंगन में पड़ोसी के भी साया जाए।

उपसभापति जी, मगर ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये सिर्फ देखते हैं कि सत्ता कैसे मिल जाए। घबड़ाए, बेचारे, परेशान लोग हैं ये। नई नई चीजें, कभी वीर सावरकर का मसला लाएंगे, कभी अफजल खान के मकबरे का मसला लाएंगे। नफरत फैलाकर ये लोग सत्ता में बैठना चाहते हैं। सत्ता जरूरी नहीं है, जरूरी है उसको मजबूती से चलाना। अगर देश को मजबूती से चलाना है तो मोहब्बत लाना पड़ेगी, नफरत खत्म करना पड़ेगी।

श्री उपसभापति: आप कनक्ल्यूड कीजिए, प्लीज।

†**श्री अबू आसिम आज़मी:** यह इंटरनल सेक्युरिटी उस वक्त तक सही नहीं हो सकती, जब तक आरएसएस, बजरंग दल पर बैन न लगा दिया जाए, इनके लोगों को बंद न कर दिया जाए। यह तब तक सही नहीं हो सकती । फिरकापरस्तों पर आपको रोक लगानी पड़ेगी।

उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए मै आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे दिल का दर्द है, मैं इस मुल्क में रहता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह मुल्क कानून से चले, किसी * या किसी * के हुकुम पर यह मुल्क नहीं चलना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*Expunged as ordered by the Chair.
†Transliteration of Urdu Script.

شری ابو عاصم اعظمی ''اتر پردیش'' : ڈپٹی چیئرمین سر، ''انٹرنل سیکورٹی سچویشن اِن اوور کنٹری'' مجھے اس پر بولنے کا موقع دیا میں اس کے لئے دھنیواد پیش کرتا ہوں۔ دیش میں تین طرح کے میجر پرابلم ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہیں '' آرگنائزڈ کرائم، ٹیرارزم اور کمیونل فورسیز''، یہ دیکھا گیا ہے کہ سرکار نے دیش میں آرگنائزڈ کرائم کے لئے اور ٹیرارزم کے لئے، اس کو روکنے کے لئے، اسپیشل قانون بنائے ۔ میسا، این ایس اے، ٹاڈا اور پوٹا۔ اسپیشل فورسیز بنائی گئی لیکن کمیونل فورسیز کو روکنے کے لئے، ان ایلیمنٹس کو روکنے کے لئے، سرکار نے کوئی اسپیشل فورس، کوئی اسپیشل قانون اس کے لئے نہیں بنایا۔ ہمارے دیش کے اندر پچھلے ۵۷ سالوں میں ۱۹۴۷ء سے لیکر اب تک اس دیش میں تقریباً ۱۳ ہزار کمیونل رائٹس ہو چکے ہیں۔ اب اسے یہ کہہ کر کہ یہ رائٹ ہے منہ چرا لینے سے یا پھر رائٹ بول دینے سے بات نہیں بنتی۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑیگا کہ یہ صرف کمیونل رائٹ نہیں، یہ بالکل ٹیرارزم ہے اور آج اگر دیش میں انٹرنل سیکورٹی کا اس دیش میں مسئلہ ہو گیا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ کمیونل فورسیز کا ہے جو اس دیش میں رہنے والے لوگوں کو دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آج دیش کی دشمن فورسز ہمارے دیش کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیرارزم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لئے فورسیز بارڈر پر بڑی محنت سے لڑ رہے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن دیش کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو ذات کے نام پر مندر اور مسجد کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے دیش کے اندر انٹرنل سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ 93-1992 کے دنگوں کو اگر دیکھا جائے، گجرات کے فساد پر اگر دھیان دیا جائے تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آئے گی مگر افسوس کہ جو لوگ دنگوں کے ذمہ دار تھے وہ حکمراں بن گئے بڑے بڑے منتری بن گئے بڑے بڑے پدوں پر بیٹھ گئے اور ان کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ دنگا کراؤ اور حکومت کرو۔ اگر پچھلے زمانے کو یاد کیا جائے، ہسٹری کو یاد کیا جائے تو جب انگریزوں کی سرکار تھی، امرتسر کے اندر جب جلیاں والا باغ کا واقعہ ہوا تھا۔ کیا تھا وہ؟ سرکار تھی انگریزوں کی، وہ غلاموں کی طرح سے بھارت واسیوں کے ساتھ پیش آتے تھے، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا ایک قانون کے خلاف جلیاں والا باغ میں بھارت ورش کے ۲۰ ہزار لوگ ایک آندولن کر رہے تھے۔ جنرل ڈائر نے وہاں گولیاں چلا کر ۲۰۰۰ سے ۳۰۰۰ لوگوں کو مار ڈالا۔ ایک چودہ پندرہ سال کی عمر کا چھوٹا سا بچہ جو لاشوں کے انبار میں دبا ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ کس طرح سے ظلم اور زیادتی ہوئی تو اس نے یہ قسم کھائی کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ جب تک میں جنرل ڈائر سے بدلہ نہیں لونگا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جنرل ڈائر کو یہاں سے لندن بلا کر

†Transliteration of Urdu script.

وہاں اسکا سواگت کیا جا رہا تھا، اسکا فیلی سٹیشن کیا جا رہا تھا کہ جنرل ڈائر نے دو سے مین ہزار ہندوستانیوں کو مارا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، صرف بدلہ لینے کے لئے اس بھری سبھا کے اندر اسے گولی ماردی۔ ادھم سنگھ کو آج ہم سوتنتر سینانی مانتے ہیں۔ اپنے دیش کا بہت جھک کر اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اس دیش کا سوتنتر سینانی مانتے ہیں۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1992-93 میں جو دنگے ہوئے اور شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ بنائی گئی، اس کے بعد ممبئی میں بم بلاسٹ ہوگئے۔ شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ممبئی بلاسٹ میں جن لوگوں کا انوولومینٹ ہے وہ 1992-93 کے رائٹ کے وکٹم تھے۔ کہیں نہ کہیں اگر ہم سنجیدگی سے اس پر دھیان دیں تو یہ ہوتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹیرارزم کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ گجرات کے فسادات کی طرف دھیان دیں تو شرم سے ہماری گردن جھک جاتی ہے، ساری دنیا میں ہمارے دیش کی تھو تھو ہوئی۔

آج بلقیس بانو اور بیسٹ بیکری کے کیسز ہوئے جن میں سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ مقدمے گجرات میں نہیں چلا سکتے اسے دوسری اسٹیٹ میں لے جاؤ۔ وہ مقدمہ دوسری ریاست میں چلایا جا رہا ہے ان کو انصاف نہیں ملا ہے، گجرات کے اندر گاؤں میں گھس کر فوسیز کے سامنے لوگوں نے وہ عورتیں جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھیں انہیں وہیں ننگا کر کے بلاتکار کیا۔ اس کے بعد عورت پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلینٹ کرتی ہے، لیکن کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی، کسی کو سزا نہیں ہوتی تو وہ نوجوان اپنی ماں کو، اپنی بہن کو ریپ ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں نفرت جوالا مکھی کی طرح اٹھے گی اور ایسے وقت میں جو ہمارے دشمن ملک ہیں جو ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں وہ لوگ اسے شہہ دے کر کہیں نہ کہیں سے اس کے ساتھ رابطہ میں آ کر، ہمارے دیش کے اندر ہماری انٹرنل سیکورٹی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے۔

شری ایس ایس اہلووالیہ : مہودے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یا تو ''سب اسٹینسی ایٹ'' کریں اور اگر ''سب اسٹینسی ایٹ'' نہیں کر سکتے تو سدن کے مادھیم سے پورے دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔

شری ابو عاصم اعظمی : کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو انٹرنل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری انٹرنل سیکورٹی خراب ہو رہی ہے۔ .....مداخلت..... دیش کی انٹرنل سیکورٹی کی بربادی انہیں نفرت

پھیلانے والوں کی وجہ سے ہورہی ہے .....مداخلت..... پھر آپ بولنا شروع کردیتے ہو.....مداخلت.....

یہ وہی * دل کے لوگ تھے جو دیش میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔

شری ایس ایس اہلووالیہ :

شری ابوعاصم اعظمی : یہ غلط بات ہے اور غلط بات کو پرشرے نہیں دیا جانا چاہئے۔

شری ایس ایس اہلووالیہ : یہ سدن کے مادھیم سے پورے دیش کو گمراہ کرنے کے کوشش ہورہی ہے.....مداخلت.....

شری ابوعاصم اعظمی : ہم سدن کے مادھیم سے دیش سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو دیش میں نفرت پھیلا رہے ہیں؟

شری ایس ایس اہلووالیہ : اس لئے یا تو وہ ان چیزوں کو ''سب اسٹینسی ایٹ'' کریں یا بتائیں کہ .....مداخلت..... کس رپورٹ میں اس کا ذکر ہے۔

شری اپ سبھاپتی : اہلووالیہ جی، آپ بیٹھئے۔ .....مداخلت.....

شری ایس ایس اہلووالیہ : آپ ۱۹۸۴ کا بھی ذکر کیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی : اس کا بھی کریں گے۔

شری دیپانکر مکھرجی : سر یہ کیا ہورہا ہے وہ اپنی مرضی سے بولیں گے.....مداخلت.....

شری اپ سبھاپتی : دیکھئے، آپ بیٹھئے آپ بیٹھئے۔

شری دیپانکر مکھرجی : وہ پہلے کھڑے ہوئے، اس لئے پہلے وہ بیٹھیں گے آپ انہیں بٹھایئے۔

شری اپ سبھاپتی : اہلووالیہ جی دیکھئے ہر ممبر کے اپنے وچار ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنے وچار رکھ رہے ہیں۔

شری ایس ایس اہلووالیہ : یہ وچار نہیں ہیں یہ آروپ ہے۔

شری اپ سبھاپتی : دیکھئے، سدن میں ایسے آروپ اور پرتی آروپ ہوتے رہتے ہیں اب اس کے لئے چیئر سے ڈائریکشن نہیں دی جاتی۔ اگر وہ آروپ کررہے ہیں تو آپ کا جب موقع آئے گا تو آپ اس کا جواب دیجئے۔ چلئے آپ بولئے۔ .....مداخلت.....

---

*Expunged as ordered by the Chair.

شری ابو عاصم اعظمی : ہم وطن کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ ہم نفرت پھیلانے والوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دلوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ سر، اس دیش میں انٹرنل سیکورٹی کے لئے پوٹا قانون بنایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گجرات میں کسی نے ٹرین جلادی، آپ انکوائری کرو اور جس نے بھی ٹرین جلائی اسے سخت سے سخت سزا دو اسے ایسی سزا دو کہ اسے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ کوئی اس طرح کی نفرت پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ انکوائری کرو تو پتہ چلے گا کہ وہ کام کس نے کیا اور جس نے بھی کیا اسے سزا دو۔ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن ۸۰ لوگ جلائے گئے تو ۱۸۰ لوگوں کو پوٹا میں بند کر دیا گیا۔ پھر ایک ذمہ دار آدمی کہتا ہے کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے اور اس کے بعد ڈھائی ہزار لوگ جلادئے جاتے ہیں، ماردئے جاتے ہیں.....مداخلت.....آپ بتاؤ کہ پوٹا کتنے لوگوں پر لگایا گیا؟ اگر ۸۰ لوگ جلنے پر ۱۸۰ لوگوں پر پوٹا لگایا گیا۔ گجرات میں ۱۸۰ لوگ پوٹا میں بند ہیں۔ ان میں ۱۷۹ مسلم ہیں اور ایک سکھ فرقہ کا ہے۔

شری اُپ سبھاپتی : اعظمی صاحب آپ کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : دوسری جگہ ۲۵۰۰ لوگ مارے گئے اور ایک کو پوٹا نہیں لگایا گیا۔

شری ایس ایس اہلووالیہ: وہی بات بتا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے.....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی : مجھے پتہ ہے۔ آپ کا جب بولنے کا وقت آئے گا تو بتا دیجئے۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی: ابھی تو شروع ہوا ہے۔ ابھی کیسے کنکلوڈ ہوگا؟ سر، ابھی دو ہی منٹ تو ہوئے ہیں! وائس چیئرمین جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل اِن جسٹس، سوشل ان جسٹس، اکنامک ان جسٹس جب تک اس دیش میں رہے گا، اس وقت تک اس دیش میں انٹرنل سیکورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہے گا۔

آج اس سدن کو طے کرنا پڑے گا کہ اس دیش میں کس طرح سوشل ان جسٹس ختم ہو جائے۔ کیا اس سے بڑی کوئی مثال اور مل سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ گجرات میں مقدمہ مت چلاؤ۔ وہاں کورٹ نہیں ہے وہاں پولیس نہیں ہے، وہاں حکومت نہیں ہے؟ مقدمہ چلانے کے لئے دوسرے اسٹیٹ میں بھیجا جا رہا ہے اور ایسی سرکاریں چل رہی ہیں۔ ایسی سرکاروں کو تو اسی دن ان کو برخاست کر دینا چاہئے۔ ایسے لوگوں کو سنتہ سے بالکل ہٹا دینا چاہئے۔ دیش کے لئے جو یہ بہت بڑے لوگ ہیں، دیش کو برباد کرنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں اس دیش میں چلا رہے ہیں اس لئے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ .....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : آپ ان کو جواب مت دیجئے آپ مجھ کو ایڈریس کیجئے .....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی: دیش کے اندر آج غریب کسان خودکشی کر رہا ہے لیکن اگر کسان کی حالت سدھاری نہیں گئی اس پر دھیان نہیں دیا گیا تو کل یہی کسان جو مر رہا ہے یہ کسان لوگوں کو مارنا شروع کریگا اور اس بات کو یاد رکھیئے کہ ظلم اور ناانصافی کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے آتنک واد.....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : آپ بولئے۔

شری ابو عاصم اعظمی: مجھے لگتا ہے کہ ''چور کی داڑھی میں تنکا''.....مداخلت.....کیا یہ وہی لوگ ہیں؟

شری اُپ سبھاپتی : آپ بیٹھئے۔

شری ابو عاصم اعظمی: ۵۷ سال سے کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔ واجپئی جی نے اسپیشل پیکج کا اعلان کیا، راجیو گاندھی نے وہاں ہیلنگ ٹچ کا نعرہ دیا۔ پورا نہیں ہوا۔ ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینا پڑیگا۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر اچھی طرح سے دھیان دیا ہوتا تو ہمارے یہاں سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج کے انڈین ایکسپریس،

دو دن پہلے کے انڈین ایکسپریس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں تو جھوٹا اینکاؤنٹر ہو رہا تھا۔ لیکن اب جھوٹا سرینڈر بھی ہو رہا ہے۔ ریپ، کڈنیپنگ، کسٹوڈیل ٹارچر پر پابندی لگائی جائے۔

شری ایکناتھ کے ٹھاکر : بم بلاسٹ پر بھی پابندی لگائی جائے۔

شری ابو عاصم اعظمی: بالکل بہت ضروری لگائی جائے۔ بم بلاسٹ پر بھی پابندی لگائی جائے اور جو لوگ بھی بم بلاسٹ کرنے والے لوگ ہیں انہیں اتنی بڑی سزا دی جائے۔ .....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : آپ بیٹھئے ایکناتھ جی، آپ جب بولیں گے تو بولئے۔ ان کو بولنے دیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : ہیومن رائٹ سنگٹھن کو کھلے طور پر کام کرنے دیجئے، یہ سب سے ضروری ہے، میں سدن کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں کچھ ہوتا ہے تو کمیشن بیٹھا دیا جاتا ہے مگر اس کمیشن کی رپورٹ کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو لاگو کرایا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ 93-1992 کی رپورٹ لاگو کرا دیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا کر رہا تھا؟ اس وقت کے میئر صاحب 93-1992 کے جو بمبئی کے میئر تھے وہ جا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیوسینا کے سپریمو کے پاس اور وہ سن رہے تھے کہ وہ ٹیلی فون پر کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج سرکاریں آج شری کرشنا کمیشن کو لاگو نہیں کیا جا رہا ہے .....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : آپ دوسری پارٹیوں کو ریفرمت کیجئے۔ بند کیجئے۔.....مداخلت..... آپ ادھر ایڈریس کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی: مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھی اس بات سے ناراض نہ ہوں لیکن سچائی یہ ہے کہ اس وقت میئر ایک اخبار والے کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، شیوسینا کے سپریموں کے پاس .....مداخلت..... جتنی زیادہ آج بارڈر پر فوسیز لگی ہوئی ہے، اسی طرح سے ان لوگوں پر پابندی لگانے کے لئے اتنی ہی فوسریز دیش کے اندر لگنی چاہئے۔ افسوس کہ ایک کیبنیٹ منسٹر، پیٹرولیم منسٹر، بمبئی جاتا ہے۔

سر، اس ملک کا پیٹرولیم منسٹر ممبئی جاتا ہے، وہاں اتنی * بڑھ گئی ہے کہ وہ وہاں پر میٹنگ نہیں کر سکتا۔ اسے واپس آنا پڑتا ہے.....مداخلت..... میں کہتا ہوں کہ کوئی دس بیس ہزار * پال کر یہ سمجھے کہ ہم سمودھان کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ دیش نہیں چل سکتا۔ یہ دیش سمودھان سے چلے گا۔ یہ دیش کسی کی * سے نہیں چلے گا، نفرت کو مٹانا پڑے گا۔اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو اعتماد میں لیکر کے.....

شری اُپ سبھاپتی : آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : بس، میرا ہو گیا۔ سر، یہ میرے دل کا درد۔

شری اُپ سبھاپتی : اعظمی صاحب، درد تو ہے، مگر وقت کی پابندی ہے۔

شری ابو عاصم اعظمی : سر، اس چمن کو خون کی جب ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی
اب یہ کہتے ہیں کہ اے اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے، تمہارا چمن نہیں

شری اُپ سبھاپتی : وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شعر بولا تو اس پر بھی آپ کھڑے ہو گئے؟ ...مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی : اُپ سبھاپتی جی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شری کرشن کمیشن لاگو ہو گیا ہوتا، اگر 1992-93 کے فسادات کے جو لوگ ذمہ دار تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہوتا تو آج دیش کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ ...مداخلت.....

شری ایکناتھ کے ٹھاکر : سر.....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی : دیکھئے جب آپ کا نمبر آئے بولئے گا۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ آپ اپنی سیٹ سے نہیں بول رہے ہیں۔ باہر آ کر بول رہے ہیں۔ اپنی سیٹ پر بیٹھئے۔ ...مداخلت..... پلیز بیٹھئے۔

---

*Expunged as ordered by the Chair.

شری ابوعاصم اعظمی : اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں....

شری اُپ سبھاپتی : اب آپ کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابوعاصم اعظمی : مجھے افسوس اس بات کا ہے آج دیش جو ہے، کم سے کم اس میں مہاراشٹر راجیہ جو ہے، وہ سمودھان سے نہیں چل رہا ہے۔ بہت گھبرا گئے ہیں یہ لوگ۔ اس لئے اگر اس دیش کی انٹرنل سیکورٹی کو صحیح کرنا ہے تو محبت پھیلانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ

ایک تجر ایسا محبت کا لگایا جائے
کہ اس کے پڑوسی کے آنگن میں چھایا جائے

اُپ سبھاپتی جی، مگر یہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یہ صرف دیکھتے ہیں کہ سنہ لیسے مل جائے، گھبرائے بے چارے پریشان لوگ ہیں یہ۔ نئی نئی چیزیں، کبھی ویر ساور کر کا مسئلہ لائیں گے، کبھی افضل خان کے مقبرہ کا مسئلہ لائیں گے۔ نفرت پھیلا کر یہ لوگ سنہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ سنہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے اس کو مضبوطی سے چلانا۔ اگر دیش کو مظبوطی سے چلانا ہے تو محبت لانا پڑے گی نفرت ختم کرنا پڑے گی۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ کنکلوڈ کیجئے، پلیز۔

شری ابوعاصم اعظمی : یہ انٹرنل سیکورٹی اس وقت تک صحیح نہیں ہوسکتی جب تک آر ایس ایس، بجرنگ دل پر پابندی نہیں لگادی جائے، ان کے لوگوں کو بند نہ کر دیا جائے۔ یہ تب تک صحیح نہیں ہوسکتی۔ فرقہ پرستوں پر آپ کو روک لگانی پڑے گی۔

اُپ سبھاپتی جی آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا، اس کے لئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میرے دل کا درد ہے، میں اس ملک میں رہتا ہوں اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک قانون سے چلے، کسی* یا کسی * کے حکم پر یہ ملک نہیں چلنا چاہئے۔ بہت بہت شکریہ۔

''ختم شد''

---

*Expunged as ordered by the Chair.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, without getting into any controversy and without generating any heat, I would like to be objective and businesslike.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You would never get into any controversy.

DR. K. MALAISAMY: Sir, thanks a lot for sparing a few minutes enabling me to join the earlier speakers who have spoken on this subject. I would like to make a presentation on behalf of the AIADMK Party, which is the Ruling Party in Tamil Nadu.

Sir, it is my profound pleasure and proud privilege to speak on a subject of all-India importance and priority, namely, internal security. Internal security deals with and mainly concerns with the safety and security of the people on the one side and protection of their property on the other. That is why safety and security and protection of property have been taken as the paramount responsibility and the prime function of any Government, and giving it top priority. What is the use of keeping everything on the earth when there is no security? When there is no protection for property.

Sir, internal security in terms of cross-border terrorism and infiltration in some parts of our States, namely, Jammu and Kashmir; insurgency and militancy in the North-East and Naxalite violence in a few States of our country have gone beyond several States. As such, it has become a national problem.

Not only that, it has become a global menace. It is a crime against humanity. Sir, the problem of terrorism or the problem of insecurity has not happened overnight. It is a legacy of over a period of several years, irrespective of the Government that came to power. Sir, I have been listening to the debate on the 7th, when Mr. Arun Shourie was initiating the discussion. He was forthright, elegant and he had been emphatic to the effect that the present Government is wanting in its efforts to control and contain the terrorists and the militants on the border areas. At the same time, Sharmaji on the other side was immediate enough to counter how this is a legacy of the previous Government.

Sir, as a person standing in between, I could say that the problem of internal security, in some form or the other, persists, subsists and continues. The sufferings of the people are going up and up. The agony and anguish have not been mitigated. On the other hand, it has aggravated. Our hon.

Home Minister, who has been giving a reply on the other day on the repeal of POTA was very eloquent. He was very calm and very collective. He was very impressive enough to say how they were maintaining internal security and trying to do their best.

Sir, they have given notes also today. I went through it. They have given various details. Sir, I agree that there is a declining trend. According to them, when you compare and contrast, there is a reduction in the incidents of violence or in the incidents of terrorism. There may be umpteen number of reasons for such occurrences as the Home Minister has already listed out. I could also illustrate the reasons that are many. And the incidents are also many. Though there can be a marginal reduction, that is not enough. The marginal reduction here and there is not going to help us. On the other hand, the real magnitude of the problem still persists.

I may list out, Sir. I have got figures of the current year for nine months from January to September. In Jammu and Kashmir the incidents of violence are as many as 2056. Then, terrorist activities, daily, on an average, are seven or eight. Then, the civilians killed are 583. Terrorists killed are 782. Major attacks are many. This is in Jammu and Kashmir.

Sir, coming to the North-East, the incidents of violence are as many as 860. Coming to Naxalites, 125 districts in 12 States are affected by the Naxalite problem. Not only that, another 24 districts are being targeted by the Naxalites. As many as 2000 core Naxalite elements are responsible for 1215 incidents of violence leading to 435 deaths. These figures will amply justify. The magnitude of the problem, and the marginal reduction, or the marginal mitigation or the slight improvement may not matter much. That is the point I want to make.

Sir, as far as causes are concerned, you could see that the causes are many. I will take half a minute on that. Sub-nationalism is considered to be one of the reasons; ethnic conflict is another cause; economic imbalance in one more cause; economic exploitation is another cause. Lack of employment also leads to this kind of terrorism and other activities, Intolerence, competition, strong currents of secessionist elements. Tribal consciousness and diversity etc. may be major causes for terrorist activities and Naxalites violence.

While listing out all these causes, it is necessary to keep the overall

perspective and features of the country. Our Indian Constitution envisages and guarantees Fundamental Rights; Not only that, it gives State autonomy it gives division of power; it gives collective rights of religious groups and minorities, giving enough right to everyone. Despite such guarantees given under the Constitution, why the security problem persists? Here I want the kind attention of the hon. Home Minister to go for deeper study of the issue. Whatever cause you have identified, whatever remedy you have concieved, something more is to be done.

Sir, as a student of Management, I have been taught that any one single problem will have more than one solution. This is how I have been taught. When I am on the process of how to find a solution, I am reminded of the famous couplet of world renowned literature, Tirukkural.

"No I NADI, NO I MUTAL NADI, ATHU THANIKKUM VAI NAD, VAIPPA SEYAL" Which means, To cure and correct a disease, find out what is the root cause, or the origin of the cause, and then you find out the source to control it, and then only it can be cured. You see how a poet of 2000 years ago was able to find a solution for each and every problem. The Health Minister is here and some of our friends who know Tirukkural so well are also here. They will apreciate that Tirukkural can give a solution to this problem also. When you envisage the root causes, you need a deep study. Whatever study you have made, whatever the bureaucracy and experts are able to suggest, you should have a different perspective and approach as far as this problem is concerned. Each problem may vary in its own way for which you cannot have a wholesale solution. On the other hand, each has to be tackled in its own way. You have to keep a new watch on that. Sir, as far as the measures to tackle this problem are concerned, I would like to say that you must have enough legal backing to do any control and containment of any crime. As far as the internal insecurity problems like terrorism, militancy, Naxalite violence etc. etc. are concerned, do you have enough legal backing, law, for that? Sir, I know law is not the only remedy. It cannot afford to be a panacea. I know it. But still you should have a law, a comprehensive law, an adequate law to deal with the situation? That is my first point.

Then I come to the next very important solution. In an explosive situation like this, one needs a political will and a skill to execute the political will. Not only that, you must have a commitment to the cause; you must have

decisiveness. I would like to ask whether the present Government has got the political will and skill to tackle this naxalism or terrorism. Sir, if I am no mistaken, I may illustrate what has heppened in Tamil Nadu. Sir, do you know that that great leader Shri Rajiv Gandhi was assassinated by LTTE in the year 1991 when Madam Jayalalitha was not in power? Immediately, when she came to power as Chief Minister, she wanted to tell the public that she has got the political will and can contain the LTTE. She took a vow to do and see that LTTE are driven out of TN within a period of six months. Sir, you believe me or not, with her consistency and political will besides employing three Ps --viz. planning, preparing and performing, she was planning very well, she was preparing very well and performing very well—the LTTE was controlled and driven out once and for all. It is a fact that is in existence from that time onwards.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, the fact is, she also supported the LTTE...*(Interruptions)*...It is on record...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): What about Vaiko?...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Mr. Shunmugasundaram, you can speak with liberty when your turn comes. I have no objection.

Sir, afterwards what has happened is a different matter.

Now, I come to the next issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malaisamy, the time allotted to your party is over.

DR. K. MALAISAMY: Sir, TNLA and TNRT are the banned organisations. They were banned since they were carrying out the secessionist movement. These groups have got close links with Veerappan. Who is Verrappan? He was the notorious forest brigand. He was the ruthless killer; He was notorious sandalwood smuggler. He was ruling 5,000 Sq. Kms. of thick forest. He was ruling and threatening the three Southern States, Tamil Nadu, Kerala, including the Deputy Chairman's State of Karnataka. Look at how our able leader, with great perseverance, was able to handle the situation. Under the eminent leadership of our leader, Madam Jayalalitha, Veerappan was killed in an encounter. The entire House knows about it. What I am trying to highlight here is this. I am not highlighting

our Hon'ble Chief Minister. I am only saying that the hon. Home Minister is a very receptive person. Whatever little solution he gets to a problem, he may grab that. Here is a case of success story. It is up to him to take the hint from the success story and use it.

Coming to another important point of solution, it relates to negotiation I often see that the hon. Prime Minister, hon. Home Minister and others have been saying, time and again, that these are the days to solve problems by negotiation. As far as I am concerned, I am not against to the cause of negotiation. Negotiation means flexibility. Negotiation means that one must be willing to give some concessions and compromise on some issues. But, at the same time, I would like to caution the Government that it should demarcate exactly where it is beyond negotiation and at what point one cannot afford to compromire. Are you not able to make it clear these aspects to the other side? In other words one must be able to say that these are the points on which there cannot be any negotiation and these are the points on which the Government is not going to compromise.

Finally, Sir, recently, we have repealed POTA. Was repealed Earlier, TADA was repealed. I am very sorry to say, that repealing of TADA and POTA is not a wise decision. They had served a very specific purpose.

SHRI V. NARAYANASAMY: Tamil Nadu misused the POTA. Therefore, it was repealed...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You need not reply to him.

DR. K. MALAISAMY: In place of POTA, one may argue that there is a substitute. This is what they are going to say. According to me, in place of POTA whatever you have substituted, it is only a substitution. It cannot become a full-fledged Act like POTA and the substitute will never serve the purpose.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malaisamy, the time allotted the your party is over.

DR. K. MALAISAMY: With these words, Sir, I would like the hon. Home Minister to have a review and re-look the whole problem and do something concrete. Thank you.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy-Chairman, Sir, I am greatly indebted to you for having given me this opportunity to speak on this very crucial, important and sensitive issue. I am also thankful to the hon. Chairman for having given permission to discuss the issue of internal security. We discussed the entire functioning of the Home Ministry in 198th Session of Parliament and since then we have had nothing on this. So, this is the right time looking at the recent killings in U.P. by Naxalities, the problem in Nagaland, discussions by Govt. of A.P. with Naxalites, etc. I wish to concentrate only on few areas since the time at my disposal is very limited.

Look at the Left Wing Extremism in the country. This has become one of the biggest menace to the country. There are as many as 12 States and 50 districts in the country afflicted with naxalite problem. The recent killings in Uttar Pradesh by naxalites clearly show that they are still in control of many pockets in the country. Take the example of Andhra Pradesh -- the most naxalite-affected State in the country. The Government of Andhra Pradesh is carrying on talks with naxalites without any fixed agenda. You wanted to discuss with the people who have killed thousands of people and who have killed 17 police personnel! Are you trying to negotiate with the extremists who tried to assassinate our leader, Shri Chandrababu Naidu? And, you wanted to share the dais with the people possessing arms in their hands and have been killing and destroying public property day-in-and day-out? Now, with the merger of the two groups, I don't know how the Government deal with this menace. After merging of these two groups, they have become even stronger. It does not mean that I am opposing the dialogue process. I am only opposing the way it is being carried out by Government of Andhra Pradesh. Sir, during the course of discussion in the Central Coordination Committee Meeting held at Bhopal on 10th May, 2003, it was observed that dialogue should be held with naxalites only when they shun violence, arms and should be undertaken from a position of strength.

Now, it is the other way round in Andhra Pradesh. Neither they have shunned violence nor have they given up arms during negotiations. No other Government, except the Government of Andhra Pradesh, initiated any dialogue with them. And, the Union Government has become a silent spectator! So, I only say that let the Union Government become a part of it, even though law and order is a State subject; and let Naxalites shun violence and arms first.

Then Sir, I come to the funding pattern of modernisation of police force. A Review Committee had been constituted for this purpose. The CCS, in its meeting held on 22nd October, 2003, had approved the funding pattern. It had categorised all the States into three categories. I would like to know from the hon. Minister what the rationale in categorising the States is; and how the Central funding pattern would be determined. I demand that one-time grant be given to the States, affected with Naxalite menace, so that they are able to modernise their force effectively because they do not match with the latest weaponry that the Naxalites have.

Then, the POLNET project, initiated by the Government, is running at a snail's pace. I would like to know from the hon. Minister how many police stations have so far been connected with the POLNET, and how many are going to be connected in the Tenth Plan. I would also like to know from the hon. Minister what are the hurdles that they have in appointing the BPRD&D as the nodal agency to oversee the modernisation of police force in the country.

Another most important role that the Ministry of Home Affairs has to play is with regard to depoliticisation of police force. For this, Padmanabhaiah Committee had been constituted in the year 2000 to identify the challenges that police would face. The Committee had submitted its report long back. What has happened to that report? What measures has the Home Ministry taken on the recommendations of the Committee? How many recommendations have so far been implemented? The House would like to know about all these things. Then, the last Chief Minister's Conference on Internal Security had emphasized on the need for structural reforms in the police force. I would like to know what are the structural reforms that the Ministry is thinking of making in this force.

Then, I wish to make a point about the Indo-Pakistan border. Out of 2,100 kms. of border, you have not fenced even 1,500 kms. This project is going on for a long time. The Ministry is fencing this border at a very slow pace. I strongly believe that this is one of the major reasons for disturbance of peace in the country. It is know to all of us that a lot of infiltration is taking place through this border, resulting in the terrorist activities in the country. Hence, I demand that the fencing work at the border should be accelerated, and it should be completed by 2005. Same is the case with

flood-lighting only about 2,000 kms. Out of this, the Ministry has so far been successful in floodlighting only about 1,400 kms. The sensitive areas are yet to be lit up. Hence, I request that this work be completed in a time-bound manner. The same is the case with the Bangladesh border. This border should also be fenced immediately.

Sir, I was shocked on looking at the Budget that had been provided to the Ministry of Home Affairs. Take, for example, the Budget for 2003-2004. Out of Rs. 16,247.28 crores, the Minister had spent only Rs. 1,615 crores as Planned expenditure. It is not even 10 per cent of the total Budget allocation! I fail to understand what plans the Ministry has in its mind to do with this meagre amount. I would like the hon. Minister to explain what efforts his Ministry has made to get higher allocations for Plan projects.

Sir, we have, for quite some time, been hearing about setting up of Federal Law Enforcement Agency in the Ministry of Home Affairs to deal with certain categories of crime, such as, illegal immigration, drug trafficking, sedition, spread of dissatisfaction against the State, counterfeit currency, funding to terrorism, etc. I do not know what has happened to that idea. I request the hon. Minister to explain to the House what has happened to that proposal. Is it hanging fire?

Sir, my next point is regarding the NSG. The main task of the NSG is to combat anti-hijack and anti-terrorist attacks. But, you have reduced it to mobile security to VIPs. Why do you want to divert this force for security when the mandate does not allow you to do so? Even the Group of Ministers had recommended for posting the CISF for VIP duties. But, you have posted them only for 'X' and 'Y' category VIPs. So, I would like to know from the Minister by when he is going to replace the NSG with the CISF.

So, these were some of the points that I wished to bring to the notice of the hon. Minister. I request the Minister to reply to each of these queries when he replies to the debate. Thank you.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आदरणीय उपसभापति महोदय, आंतरिक सुरक्षा की बहस पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं इस बहस में आरोप-प्रत्यारोप के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। ...(**व्यवधान**)... यह परिहास का कारण नहीं है, शांत रहें। उसका मुख्य कारण यह है कि आंतरिक सुरक्षा आज सारे भारत के लिए चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय के कारण, मखौल उड़ाने वाले उड़ाएंगे, किंतु इसी आंतरिक सुरक्षा ने

इस देश का एक प्रधान मंत्री मार डाला, एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री मार डाला, एक मुख्य मंत्री मार डाला और पता नहीं, कितने ऐसे राजनैतिक कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर, राष्ट्रवाद से ...(व्यवधान)... अरे भाई, चुप रहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उन्हें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मुझे आपसे ज्यादा इतिहास पता है, आप अखबार में लिखा करते थे। महोदय, आज जो सारी दुनिया चल रही है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें कोई भी देश अब किसी और देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उस पर आक्रमण नहीं करता या उसका अधिग्रहण नहीं करता। उसका कारण यह है कि किसी और पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसकी ज़मीन को हथियाने के साथ-साथ वहां की जो पॉपुलेशन आती है, वह लायेबिलिटीज लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाती है, मिज़रीज़ लाती है। इसीलिए आज लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम देश की जनता के दिमाग पर, उन लोगों पर कैसे अपना आधिपत्य जमा सकें-उसके दो रास्ते हैं। एक है आतंक, टेरर और दूसरा है कि डिफरेंट आइडियालॉजी उसके ऊपर थोपी जाए। उसकी पेट्रियॉटिज्म और नेशनलिज्म की भावना को समाप्त करके कोई नया इज़्म उसके ऊपर थोपा जाए और यही कोशिश हमारे देश में चल रही है।

महोदय, मेरी पूर्व वक्ता दुर्गा जी कह रही थीं नक्सलवाद के बारे में। जैसे वे आंध्र प्रदेश से आती हैं, नक्सलवाद से ग्रसित हैं, वैसे ही मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई -लिखाई पश्चिम बंगाल में हुई है। नक्सलवाद को मैंने करीब से देखा है। नक्सलवाद के पहले कार्यकलाप की नॉर्थ बंगाल में नक्सलवाड़ी से शुरुआत हुई और फिर बढ़कर वह साउथ बंगाल अर्थात मिदनापुर के गोपी बल्लभपुर में पहुंचा और उसके साथ-साथ श्रीकाकुलम पहुंचा, जहां से दुर्गाजी आती हैं। आज माओ-त्से-तुंग का नाम लेकर जिस चीज़ का प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, मैं उस पर थोड़ी देर बाद आता हूं, पर मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला या हमारे उत्तर-पूर्व का मसला, यह तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से चला आ रहा है। अलगाववादी ताकतें वहां पर अलगाववाद करके देश के टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश करती हैं। हमारे देश पर यदि बाहर से आक्रमण होगा तो उसको संभालने के लिए, हमारी सरहदों पर तैनात, हमारे रण बांकुरे फौजी जवान बैठे हैं। वे अपनी कुर्बानी देकर भारत माता की रक्षा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के कारण, देश के अंदर जो हो रहा है, दिन-प्रति-दिन खतरा बढ़ रहा है, जिसके बारे में मैंने आरम्भ में भी कहा है कि इसके कारण हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री और एक मुख्य मंत्री को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। एक मुख्य मंत्री चन्द्रबाबू नायडू, जिनकी गाड़ी बम से उड़ा दी गई थी, बाल-बाल बचे थे। महोदय, उनकी बात तो अलग की जा सकती है, किन्तु यह तो जी॰ई॰सी॰आर॰ है, अर्थात् Great Equalitarian Cultural

Revolution of China की बात करने वाले लोग हैं, जहां माओ-त्से-तुंग के पुतले हटा दिए गए हैं, उनकी मूर्तियों को हटा दिया गया है, लेकिन उनका भारत में नाम जपने वाले ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? महोदय, 1967 से ये लोग बढ़ते गए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्री महोदय ने एक टिप्पणी बांटी है, कुछ रेमार्क्स बांटे हैं, उसमें उन्होंने 2001 से उल्लेख किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि 1967 से लेकर इसका फैलाव पंजाब तक हो गया था। एक वक्त ऐसा आया कि यह पंजाब का रूरल पंजाब नक्सलवाद की चपेट में आ गया था। लोगों ने नक्सलवाद से बचने के लिए रिलिजियस फंडामेंटलिज्म शुरू किया और नक्सलीज्म को टोटली कन्वर्ट कर दिया, वही नक्सलाइट्स रिलिजियस फंडामेंटलिस्ट होकर उभरकर आए हैं और उन्होंने एक खतरा पैदा कर दिया था। ये कहते हैं कि " on the question of strategy", Leninist और Maoist क्या कहते हैं,

"on the question of strategy, it opposed the path of peaceful transition put forward by CPI & CPM and upheld the path of Protected People's War".

जो बार-बार कहते हैं कि हमें इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से रास्ता नहीं निकालना है, बन्दूक की नाल से पॉवर निकलेगी और आज उसी से सबसे बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। लेकिन इस खतरे के बारे में ...(व्यवधान)...

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): This is the difference between CPI (M) and Naxals.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I know that. I know the difference between CPI (M), CPI and Congress. मैं वह दिन नहीं भूला हूं, जब 1967 में एक ऐसा मौका आया कि पश्चिम बंगाल का कोना-कोना नक्सलाइट हो गया था और 1972 में सी॰पी॰एम॰ के लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया था।...(व्यवधान)...

SHRI MATILAL SARKAR: He is not correct ...*(interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: One minute. Let me complete the sentence. 1967 से लेकर 1972 तक कितनी सरकारें पश्चिम बंगाल में बदली गईं, उसका क्या कारण था? उसके बाद आप ही ने लिखा, आपके नौजवानों ने लिखा कि 'सत्य सेल्युकस, विचित्र है यह देश'। ...(व्यवधान)...

SHRI MATILAL SARKAR: Don't tell us untruth.

SHRI S.S. AHLUWALIA: लिस्टन टू मी, You are born only after 1964.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: आप पहले पैदा हो गए थे क्या?

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is the most dangerous pact in the sense 'सत्य सेल्युकस, विचित्र है यह देश, 70 में नक्सल, 72 में कांग्रेस'। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों से लिखा हुआ दीवार लेखन है, शायद दीवारों से चूना उतारने पर, वह लेखन निकलेगा। यही कारण है कि आज आन्ध्र प्रदेश में भी कांग्रेस ने पी॰डब्ल्यू॰जी॰ से समझौता किया और गृह मंत्रालय के बड़े अफसरान कहते हैं कि मोस्ट डेन्जरस पैक्ट, मोस्ट डेंजर्स पैक्ट इन दि सेंस, एम॰सी॰सी॰ और पी॰डब्ल्यू॰जी॰ का जो पैक्ट हुआ है, उसको मोस्ट डेन्जरस कहा जा रहा है। मोस्ट डेन्जरस कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम्पेक्ट रेवोल्यूशनरी जोन की घोषणा की है। इनका यह कम्पेक्ट रेवोल्यूशनरी जोन आंध्र प्रदेश से लेकर नेपाल के माओवादियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह खतरा सिर्फ नेपाल के राज परिवार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि यह खतरा हर भारतवासी के खिलाफ पैदा हो रहा है। आज मेरे खयाल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि बहुत वर्षों बाद कलकत्ता में उनकी रैली हो रही है। कलकत्ता में यह रैली इनके दिल की धड़कन बढ़ा रही है। राइटर्स बिल्डिंग में भी धरधराहट पैदा हो रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं और कहां से आ रहे हैं। परंतु मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 1967 में पैदा हुई यह संस्था, 1970-72 के बीच कांग्रेस के साथ इनका जो समझौता हुआ, ये इतने ताकतवर हो गए, ये लोग कैसे आगे बढ़े, यह देखने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि हम इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान क्यों नहीं देते। हम इंटरनल सिक्योरिटी को आपका रिजीम, मेरा रिजीम या उसका रिजीम क्यों कहते हैं? मैं अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखूं तो भारत में तीन बार इमरजेंसी लगी है– 1962, 1971 और 1975 में। 1962 और 1971 की इमरजेंसी के लिए यह कहा गया कि चाइना और पाकिस्तान से जो लड़ाई चली थी, वह इसलिए लगी थी। किन्तु 1975 की इमरजेंसी को हमने इंटरनल डिस्टर्बेन्स कहकर लागू किया। संविधान के 44वें संशोधन में, जब जनता गवर्नमेंट की सरकार यहां आई, 1978 या 1979 में 44वां संशोधन जब पास किया गया, तब इंटरनल डिस्टर्बेन्स को आर्म्ड रिबेलियन कहा गया। जब तक आर्म्ड रिलेटिड रिबेल नहीं हो तब तक इमरजेंसी घोषित नहीं हो सकती। परंतु दुर्भाग्य की बात देखिए कि 1971 में हमने एक कानून पास किया, जिसका नाम था "मेंटनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट"। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग उस सिक्योरिटी एक्ट के तहत बंद हुए होंगे, मैं भी अपने छात्र आंदोलन में उसी "मेंटनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट" के तहत कांग्रेस में रहते हुए बंद हुआ था। मुझे पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए प्रावधान रखा गया था, उससे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बनाए गए। जब हम इधर, 1990 के दशक में आते हैं, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए तो एक वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई। इस वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी गईं। वैसे तो उसकी शुरुआत ऐसे की गई थी कि एक आतंकवादी, एक स्मगलर, इकबाल मिर्ची के बारे में पता लगाना है, किंतु पता लगाते ही जैसे मधुमक्खी का छत्ता ही खुल गया हो। बहुत सारे लोगों के नेक्सस के बारे में पता चला। स्मगलर, टेरेरिस्ट नेक्सस, पुलिस नेक्सस,

3.00 PM

कस्टम ऑफीसर्स, आई०ए०एस० आफीसर्स, पोलिटिशियन्स, ईवन ज्यूडिशियरी के नेक्सस के बारे में पता चला, परंतु इसके जो एनेक्सचर्स थे, वे आज तक सदन में नहीं रखे गए, आज तक सदन में उस पर बहस नहीं हुई। हम ऊपर-ऊपर ही एग्जूकेटिव समरी पर बात करते रहे। मैं समझता हूं कि शायद वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में जिस नेक्सस के बारे में लिखा गया था, अगर उस नेक्सस के बारे में पूरी इंक्वारी की जाती और कार्रवाई की जाती, सुधार किया जाता तो शायद हमारे आने वाले दिन उज्जवल होते, हमारा भविष्य उज्जवल होता। किंतु हम अभी भी इसे मान नहीं रहे हैं। इसके बाद 2000 में भी इंटरनल सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट आई, जिसकी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट भी आई, किंतु हम अभी भी पीछे छूटे हुए हैं। 11/9 के कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उस कमीशन की रिपोर्ट में सारे विश्व के लिए एक गाइडलाइन बनाकर दी गई है। क्योंकि डिजास्टर दो तरह से होते हैं, एक डिजास्टर या तो नेचुरल कैलामिटी के रूप में आएगा, अर्थक्वेक होगा, साइक्लोन होगा, बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी। और एक disaster, man-made होगा, जो आतंकवादी घटना होगी। उस disaster को मैनेज करने के लिए, गृह मंत्रालय में जो disaster management committee बननी चाहिए, मेरे ख्याल से आज भी हम उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

महोदय, हम NCC के लिए अपने नौजवानों को तैयार करते थे ...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के लिए जितना समय निर्धारित था, वह पूरा हो चुका है, अभी आपकी पार्टी की तरफ से 3 और वक्ता बोलने वाले हैं, इसका ख्याल रखते हुए आप बोलिए।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि NCC और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देकर, टैररिस्ट्स से combat करने की जो disaster management योजना होनी चाहिए, वह नहीं है। आज जो आतंकवादी घटनाएं उत्तर-पूर्व में हो रही हैं, कश्मीर में हो रही हैं, उनके लिए तो भारी-भरकम खर्चे हैं, भारी-भरकम कमेटियां हैं, भारी-भरकम सोच-विचार है, किंतु नक्सलवाद को संभालने के लिए कोई योजना नहीं है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से गृह मंत्री जी भी अवगत होंगे कि ISI ने नक्सल आर्गनाइजेशंस और "अल-कायदा" से हाथ मिलाकर एक trio-link बनाया है। उस trio-link में कल को कोई भी खतरा पैदा हो सकता है। इनके जो वालंटियर्स हैं, इनका जो नैटवर्क है, वह जबरदस्त है, क्योंकि आज जो टैररिस्ट हैं, वह पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसकी नैटवर्किंग सारी दुनिया में है और वह रिमोट से काम कर रहा है। यही कारण है कल असम में series of blasts हुए, इसी तरह जब 1993 में मुंबई में series of blasts हुए थे, तो हमें अंदाजा नहीं था कि series of blasts करने वाला कौन है? सारे विश्व में आप देखिए कि series of blasts करने वाला, उसको design करने वाला एक ही आदमी है, जिसका नाम FBI की website पर लिखा हुआ है, मैं यहां उसके नाम का उल्लेख

नहीं करना चाहता हूं। उसका नाम बिन लादेन के ऊपर लिखा हुआ है। यह बताने की जरूरत है कि ऐसी चीजों से मुकाबला करने के लिए हमने क्या तैयारी की है। हम एक-दूसरे पर आरोप करें, यह अच्छी बात नहीं है। महोदय, UN में जो CCT कमेटी है, भारतवर्ष उसका एक हिस्सा है, मेंबर है, उसका signatory है। अगर हम अपने आपको पीछे धकेलते हैं, अगर हम वोट बैंक की राजनीति में फंसकर यह कहें कि इस कानून को जरा कमजोर करने की जरूरत है, न कि इसको ताकतवर बनाने की जरूरत है, तो इससे यह समस्या नहीं सुलझेगी।

उपसभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से गृह मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि आंतरिक सुरक्षा का मसला, एक ऐसा मसला है जिसको आप अकेले बैठकर नहीं सुलझा सकते हैं। अगर आप जरूरत समझें तो आप विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर एक समिति बनाएं, उस पर आलोचना करें और आलोचना करके, इसके लिए एक रास्ता निकालने की जरूरत है वरना आने वाले दिनों पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भारतीयता को बांटने की कोशिश न करें, हम भारत को एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत बनाकर खड़ा करने की कोशिश करें। हम बाहरी सुरक्षा के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान, हमारी सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर हम सिर्फ IB की रिपोर्ट या RAW की रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे, dependence on paramilitary force, curbing this, curbing that . ... तो शायद हम इसमें सफल न हों क्योंकि एक आतंकवादी जो होता है, वह मरने या मारने के लिए आता है। इसी तरह के हरेक नागरिक को अपनी भारतमाता की रक्षा करने के लिए, मरने या मारने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी हम आतंरिक सुरक्षा कर सकेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for affording me this opportunity to participate in a debate of vital importance. Sir, a debate on national security must truly be a national debate, not subordinated to any partisan agenda or to any political agenda. In fact, the *raison de'tre* of State and the foremost obligation of governance are to secure the security of its citizens and the territorial inviolability of its borders. Eventually, it is this measure that determines the legitimacy of the exercise of State Power and our quest for political power and right to govern. I also believe, Sir, that the matter of security is the foremost legitimate concern of each and every citizen of this country who amongst themselves are the ultimate sovereigns to which democratic power ought to be accountable. It is in this broad frame of reference that with your leave I seek to make my submissions. Sir, before I proceed to deal with the specifics, it is necessary to draw the contours of the debate. Sir, internal

security of any country today in a globalised world cannot be divorced from the external security environment. Sir, I have it on the authority of Jane's Intelligence Review, the foremost Intelligence and Defence Journal, on the authority of the US State Department's Report of 2002, that from Bali to Grozny to Mambosa, that is, all throughout the world nation-States are under pressure from terrorist activities. It is a reality, we cannot shirk. It is a reality, we cannot escape, and we see its overhang on our internal security environment; we see its overhang on the regional security environment. We are almost certainly on the receiving end of Pakistan-sponsored ISI's cross-border terrorist activity. Closer home, we cannot ignore Maoist violence in Nepal; infiltration from Bangladesh into our country which has certainly altered demographic profile which has led to alienation in certain parts of our country. We cannot but be concerned with the internal Islamic fundamentalism in Bangladesh and its inevitable reverberations in our own country. But what concerns me most, Sir, -- and this is clear in our own Annual Report of the Home Ministry -- is that the extremist violence in parts of our own country is something that grew over the last few years. This Government, in a sense, inherited a very difficult security situation. In the North-East, we have trouble spots. In Assam, Meghalaya, and Manipur, we have serious problems. In Karnataka and Tamil nadu, when we talk of the compact revolutionary zones, we see the Naxalities insurgency and the extremist insurgency spreading from Telengana to Bihar, and likewise we have problems in eastern Uttar Pradesh and all of these activities, cumulatively and individually, ought to be a matter of concern, and indeed they are, That is why, Sir, we have this debate on a grave issue in the highest fourm of our democracy. Sir, this Government is called upon to answer for what it has done or what it seeks to do to address this problem. I will presently come to the initiatives which this Government has taken and I am sure that a lot more needs to be done and will be done in the months ahead. But, Sir, the primary question, that we need to ask ourselves, is what are the root causes of the escalation of internal discontent that has led to the increase in the dissatisfaction, in disaffection and, therefore, violence. Sir, one does not have to be a philosopher; one does not have to be a political thinker to realise that somewhere, perceptions of injustice lead to discontent of a nature that, in turn, breeds violence and incites people to take to arms. And, that, Sir, is the root cause of our internal security problem. As was stated by the distinguished speaker who preceded me, our soldiers on our borders are

competent, equipped and committed to repel any aggression from across the border. But, once, it comes to dealing with an internal security problem, it is a matter that does not admit of one aspect or facet; it is the totality of the situation that needs to be addressed, and, therefore, delicately handled and it is for this reason, Sir, that the hon. Prime Minister, on assuming office, said that our approach would be humane, our approach would one of firmness tempered with compassion, our approach would be one which would seek an inclusive society, that would reach out to those who are dissatisfied in an attempt to bring them back into the national mainstream. It was this approach, in the Rajiv Gandhi years, that led to Assam and Punjab Accords, and it is this approach that enables this Government to deal with Manipur, to deal with ULFA in Assam and to deal with the situation in Meghalaya and elsewhere. I would like to commend the hon. Home Minister and the Prime Minister for their initiatives in making the first trips to the troubled spots in Jammu and Kashmir, to Manipur and to the North-East. And, what did the hon. Prime Minister do when he went to J&K? He met with all and sundry; he met with all the groups that he thought would benefit the cause of Jammu and Kashmir. He announced a package of Rs. 24,000 crores over four years only with a view to say that the Indian State, while fully equipped to deal with a firm hand with those who challenge its sovereignty, will also try the peace process and negotiate itself, and that is why, we have now extended the opportunity of a dialogue to the Nagas. So, it is an all-encompassing approach that we have adopted, we need to adopt, and that, Sir, in my view, is the only way to deal with this problem. Sir, a few factors which, I thought, I need to mention very briefly in a minute. Sir, when I talked of the situation that leads to internal dissatisfaction, it is the sum total of the aberrations that have crept into our body politic, the aberrations that seek to erode the core values of our body politic. Sir, Gujarat was indeed a frontal assault on the secular soul of this country. In fact, the communal alienation, the polarisation on communal lines did threaten the internal solidarity of this nation, and, Sir, a house divided against itself, can never stand. I am not apportioning blame for whatever reason it happened; it happened. The people of India have given their verdict. They have spoken up. But, now we have to get on; we have to ensure that these aberrations are nipped in the bud and not repeated lest our unity, our integrity, our solidarity, our strength and our democracy, and our future itself, come under siege once again. Sir, the political interference in law enforcement, ...(Time-bell)... the question of

electoral reforms to rid the body politic of the unholy nexus between the political establishments and criminals, and, the issue of benign laws; all these are very much a part of the agenda, and, ought to be a part of the agenda to comprehensively address the internal security problem.

Sir, when we talk of security, we talk of food security, we talk of unemployment, we talk of energy security, and, we talk of external security and internal humanisation of society. No debate on internal security, I dare state, can ever be complete, can ever be purposive, can ever be meaningful, and, can ever be useful if it were to be confined to aspect 'a' or aspect 'b'. Therefore, the totality of the circumstances has to be addressed, and, in that light the approach that I briefly described in the opening is, in my view, the right approach.

I do want to make a few points with respect to what Mr. Arun Shourie stated in his intervention. He made three points. In reference to the amendment of POTA, he said, 'Don't ferment a permissive environment'. Perhaps many of my colleagues and friends don't know that my Ph.D. has been in the legal control of the international terrorism. I have a little theoretical knowledge of security issues, and, I come from the State of Punjab where we experimented with TADA. Sir, if today, we are rid of terrorism in Punjab, it is not because of TADA, and if today, we have failed to eliminate terrorism in other parts of the country, it is not because of POTA being there on the Statute book. Everyone knows that oppressive laws ferment dissatisfaction, they breed violence, they compel people to resort to extra-constitutional and extra-legal means because of the perception that the existing legal frame of reference is inherently oppressive, and, is incapable of delivering justice. Therefore, my answer to my esteemed friend, Mr. Arun Shourie would be that the elimination of oppressive laws is a step forward in securing our internal security environment, in getting rid of terrorism.

The second point that he mentioned is: please talk, and, by all means, talk to everybody, but don't be befooled into believing what is said to you across the table. I completely agree, Sir. I completely agree. It is nobody's case that while you negotiate your case with those who challenge your authority, with those who threaten your sovereignty, you should lower your vigil. Sir, this Government has never lowered its vigil, and, that is borne out by the fact of our defence preparedness, that is borne out by the fact that

our intelligence agencies are doing a much better job, and, Sir, the figures that I have...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ashwani Kumar, you have to conclude now.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I will take only two minutes. Sir, the figures that I have with respect to Jammu and Kashmir amply prove my point.

Sir, in 2003, the number of infiltrations in Jammu and Kashmir was 120, and, in 2004 the number of infiltration came down to 100. In 2003, the number of infiltration bids foiled was 47, and, in 2004, this was 38. In 2003, the number of extremists killed in bids foiled was 162, and, in 2004, it was 84.

Likewise, Sir, in North-East another trouble spot, in 2003, the number of incidents was 1124, and in 2004, it was 905. Sir, in 2003, the number of extremists killed was 409, and, in 2004, it was 313. All of this goes to show that the initiatives taken by this Government in the short period of six months has delivered the desired results. Sir, I would conclude by saying that while the Union of India, the Central Government, is at all times prepared to assist the State Governments, in whatever manner required, to counter terrorism and in aid of the internal security of the States, the principal responsibility remains with the States, and I do not say to shirk responsibility for the Central Government. I say so because that is the only position consistent with the federal structure that we have given to us, consistent with the list of responsibilities that the three lists enumerate, and in order to ensure that there is no encroachment on the legitimate spheres of the State and in order to ensure that the federal polity remains sacrosanct. Therefore, Sir, in submission, I would only like to say that in the short period of six months, this Government has indeed taken the intiatives as expected of it, required of it and I have no doubt that, in his reply, the distinguished Home Minister will further satisfy the House that all, that is required to protect the internal security of this country, will indeed be done. Thank you.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, internal security, as we all, I am sure, understand, is really an ongoing process. So, whatever we are facing today is nothing unique,

nothing new. Other Governments have faced other problems in their own time. In today's environment, I think, this Government, which is in office today, has got some bright spots. for example, as a result of prolong negotiations with the Nagas, today, we find, when Mr. Muviah and Mr. Issac Swu deplaned at Dimapur, they made a clear declaration to the people waiting to met them, "we have got to be realistic in finding a solution for Nagaland". This has not happened in the last two months or the last one year. It has happened over fifty years. So, today, I think, there are bright spots, and there are dark spots also. We have the High Court of a State condemning its own Government that the law and order situation is totally out of control, the High Court of a State telling its own Government to carry out raids inside the prisons without associating the local police force. So, I do not think we need to be unnecessarily pessimistic about the overall State of internal security; nor indeed, Sir, must we be too optimistic about it. It is an ongoing process. In passage of time, it will be sorted out. And, if past events are any guide, there will be no problem. But that is a part of the game, a part of the governance, and it will carry on. The dividing line between internal security and law and order is extremely thin. Internal security, very often, is an intensification of a law and order problem. A person who calls himself a militant is also a bank robber; a drug smuggler sometimes obtains cover for his activities declaring himself to be a part of a militant movement. In any case, raising resources by any militant movement involves an extensive element of, what we call, criminal activity. So, the dividing line, there is a lot of interaction between internal security, between law and order, between organised crime, and all of these trace their links to a delayed and, I would say, disintegrating process of dispensation of justice. Today, therefore, I emphasise the point made by the distinguished speaker in front of me. I think, we have got to focus, the Minister of Home Affairs has got to focus, on the role of the States in combating internal security because the primary responsibility for law and order, which contributes to increasing or decreasing internal security, is that of the State. Here, I am afraid, the records of various States in mutual cooperation, in mutual coordination, have been extremely variable. I do not think it has been a good record. It has reflected, from time to time, on the state of Centre-State relationships depending upon the Government that have been in power in the States and at the Centre. I would like to say that during the previous dispensation, when the previous Government was at the centre, almost the inter-personal relationship between dignitaries in

the States and the dignitaries at the Centre were not good. It was reflected on the various meetings. When the then hon. Home Minister called for a meeting of the Chief Ministers of all the States to discuss the internal security situation, it was not nice to see that a large number of Chief Ministers absented themselves, not even sent any representatives. It may be politics, but it is not good for the country.

Today, I think, one issue on which the Central Government, through the Hon. Home Minister, has to focus very hard is to work along side the States. Within the States too, their performances, whether it is law and order in those States which are afflicted with internal security problems, or others have been variable. I do not think any State can claim to have successfully combated the law and order problem, or the internal security situation. The Central Government is duty-bound, and has been doing it indeed, to aid the State Governments to control the law and order problem, to assist them. But I am afraid, most of the States, with only a few exceptions, have not made good use of assistance provided to them by the Centre, whether the earlier Central Government or even this Government. The major issue, therefore, flowing from this is, I think, we must discuss and understand that until the State Police become capable of fighting crime as well as terrorism and militancy on their own, internal security situation will not be a matter of satisfaction. There has been a great deal of emphasis laid on the upgradation of State Police. Sufficient resources have been allotted to them. But as we understand from figures provided to us, several States, including some which are affected by militancy, have either not spent the amount allotted to them, or have not utilised it for various reasons, and have returned these resources unspent. With such an approach, I do not think, the Government of India can ever hope to contain the internal security situation in this country.

I think, we have a peculiarly short-sighted approach to what we call 'the modernisation and upgradation' of the State Police. Mere provision of weapons, or supply of weapons, or communications equipment, or vehicles, or accommodation will not do. What needs to be done, more urgently perhaps than the supply of weapons, or equipment, or any other physical resources, assets for the State Police, is the upgradation of their leadership. I hope, I am not making a sweeping statement. But I do feel that the leadership of the State Police is extremely poor. It is not only poor, but it is extremely poor. And that is brought out from the performance of almost all

State Police forces in confrontation with militants, in confrontation with armed criminals.

So, I do believe that along with the supply of equipment, the Central Government...(*Interruptions*)... Would you like to say something, Sir ? ...(*Interruptions*)...

DR. FAROOQ ABDULLAH (Jammu and Kashmir): Yes, I am on a point of order. Sir, I had been the Chief Minister of one of the States affected by militants. What the General is saying about militancy, I would like all to remember that we are all politicians. It is not the Army that rules the States; it is the politicians who rule the States. The General has no experience of politically running a State. Therefore, when he is levelling charges about State Governments and their functioning, I will remind him of something which I didn't want to do, but I would tell him. I hope you will not take it as amiss. Sir, in my Government, I wanted to have a Unified Command, Unified Command was necessary because I wanted all the agencies of intelligence to be put under one agency so that would be functional and would be able to get information and the action to be taken. Sir, the biggest block was the Army itself. When I asked for a Unified Command to be put with the Army General in command, the greatest opposition came to me from the Defence Ministry itself. They did not allow. They said, "No, you take a retired General who would head this organisation". And I felt that a retired General the minute he lets his office down, he no longer is able to control the information, nor is he able to guide the movements that have to take place. I would like to remind the General that at that time, it was not the politicians who failed, it was not the Union Government that failed, but it was, unfortunately, the decision that the Army took, at that time, and refused to give a sitting General as the command of the Unified Command. And I must say to this House and the hon. Minister who has seen the unified Command, it has done as well in Jammu and Kashmir that they had to then decide to do the same thing in Assam. I would like to kindly request the General don't make a sweeping statement about politicians are not being trained; politicians are well trained; they know what their job is. The tragedy of ours is that we are trying to blame each other. That is not the way of functioning of this House. This House is meeting today because it wants to find solutions as to how to combat it, how does the General expect me to combat terrorism when Pakistan continues to beat us, when Pakistan continues to send militants

across the border? How do I fight it? It is not a question of only one thing. I want this House to remember this thing. It is not only the political Government that has failed; it is all of us who have failed in that.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: May I refer to your...(*Interruptions*)... अपनी बात ही कहेंगे, Hon. Farooq Abdullah is absolutely right. He is absolutely right. But I would also like him to remember regarding the Unified Headquarters in Kashmir, when he was elected back as the Chief Minister, there was some dialogue and it is we who insisted -- I am sorry, not we, but Army. There were Unified Headquarters to ensure that all agencies worked properly, should be headed by the Chief Ministers of the State, in which, the Formation Commander and others like Director-Generals, Inspector-Generals and all that. As a matter of fact, if the hon. former Chief Minister would remember, it was the Army that advised that there should be two Unified Headquarters -- one based in Srinagar and one based in Jammu -- because it was realised that it would spread outside the valley. So, I accept what he is saying is absolutely correct. But then it was the advice of the Defence Forces. I did not say the politicians were badly failed, I said the police. And the tide is turning in Jammu and Kashmir, the tide turned in Punjab because the police could now start taking charge of the situation. When that stage comes to other States, you will be able to solve your internal security problems. That is exactly what I am saying. Until that stage comes, it will not be solved. So, what I was saying was that the police leadership has to be improved, not merely by a provision of equipment, but by upgrading their leadership. The crux of the issue— I am sorry to repeat this point—is that why is the Army more successful than the other forces? It is a very basic question. It is the leadership, and until the State police forces, the paramilitary forces, the Central police organisations improve their leadership, we shall always be handicapped in the fight against internal security. So, I would request the hon. Home Minister to please give a thrust, through the State Governments, on improving the frontline upfront leadership of the State police forces. I will certainly say this much inspite of what the hon. former Chief Minister of Jammu and Kashmir has stated that the police forces are highly politicised in the States. I do not know what the answer for this is. Until that is done, they shall continue to do be so. I would also like to comment on a few issues. What has happened to the Central Reserve Police Force becoming the primary internal security force in the country? The programme is there. A

beginning was made. Then it had to be withdrawn because, for some reasons, they were not yet fully trained for the task. It is on this, and they will never be up to the mark, until the leadership is improved. I would like, through you, Sir, to request the hon. Home Minister to please see that the CRPF is upgraded, both in equipment as well as in leadership, to assume the responsibilities of combating internal security, in some cases, of combating organised crimes, which in many States have almost assumed the status of internal security. Through you, Sir, I would like to request the hon. Home Minister to see to it that the Border Security Force is put back on the borders, with particular reference to the eastern border with Bangladesh. This objective, which was stated a number of times, has not yet been achieved. We, who live in the eastern States, note to our dismay, that the border security forces are brought in; thereafter, when there is some kind of emergency somewhere or elections are there or the CRPF has to be reinforced, they are pulled out again. Please do not treat the eastern border as a priority two threat. It has as much a priority as the western border. Please put the BSF back. I would like to suggest to the hon. Home Minister that we do need a 'Federal Police Force', and my State is a particular victim to that, because, we find criminal gangs, plain criminals, they are not very, very sophisticated, they are plain criminal gangs, who come from other States— I am talking of my own State, the State of West Bengal,— they commit most outrageous crimes over there and disappear back into their home State. Today, under the present procedure, a police party from the police station, where the crime has occurred in one State, is sent to the State from where the criminal comes from, and I think, a large number of cases are nullified because they cannot do it. Again, without attempting to draw comparisons with other countries, anywhere in other countries, and at least, in one country, where, if a criminal flees across the State line, it becomes a Federal crime. I think, we have to look at it, and I fully agree that the law and order is a State subject. But given a peculiar circumstance, we will have to look into how best to create a Federal Police Force, which can operate across the State boundaries. Within the States, the police forces find it difficult to operate across the *thana* boundaries, and you will have to try and find out some way where the police forces can operate interruptedly across the State boundaries. A federal police force, to me, is the answer. Can you possibly consider combining the investigative powers of the CBI with the manpower of the CRPF for creating such a force? I do not know; I am just speaking of

things off the cuff, but I think a federal police force and a federal investigating agency is a necessity. How we go about it keeping our Constitution in mind is something that the Government will have to devise.

Sir, I would like to say a few words about the Naxalite movement. The Naxalite movement, I think, by common consent, is the main threat which is menacing the State today. In some senses, without appearing to trivialise the other problems, it is more dangerous than the situation in Kashmir or the situation in the North-East because, geographically, Kashmir is in the north-west corner of the country. As indicated, the State is in the extreme North-East. The heart of the country carries on moving in spite of these two areas. Your Bombay Stock Exchange reaches the top limits in spite of Kashmir, in spite of the North-East.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRIMATI SARLA MAHESHWARI) in the Chair.]

But if God help us, if the Naxalite movement ever catches on, it will split the country in half. You won't be able to go from Delhi to Calcutta or from Bombay to Madras if this movement ever catches on. So, I do think that a lot more urgency, a lot more coordination and a lot more effort and attention must be devoted, from now onwards, on containing the Naxalite movement. I do not see any evidence of that at present. I see each State making individual efforts on its own pattern. These are scattered; these are inadequate, and unless the Central Government manages to get the States act in coordination, I am afraid, Sir, given a few more years, the country will have to pay a very, very heavy price.

Again, Madam Vice-Chairperson, through you, I would like to reiterate that the Naxalite movement would not go away unless its root causes are examined and addressed. One of the root causes of the Naxalite movement is continuous neglect, for the last 55 years, of the tribal regions of this country. They are almost exclusively focussed in areas where there are tribals. There must be some reason for that. It is because the successive Governments and the successive States have treated our tribal population as second-class or third-class citizens. This will not do. While elections will continue to be fought on various reasons, the development will/shall continue to be an election issue. But I do feel that unless this Government or the previous Governments fail to deliver on development for the tribal regions, we will face this catastrophe again. So, I would repeat a suggestion,

which I have been trying to make wherever I have been able to put it across, please do seriously consider converting of these tribal areas into special development zones into which Central/State resources must be funnelled, and some kind of a *modus operandi* must be worked out where these development efforts are monitored from at frequent intervals so that those particular trouble spots can be brought up and, hopefully, the root causes like the sense of injustice of Naxalite troubles, which these regions are suffering under, can be dealt with. I am, by no means, suggesting that a purely law and order approach should be taken towards the Naxalite problem. But it has to be both.

One cannot be at the cost of the other. So, I do think that unless we focus our attention on this, unless the Centre and the State Governments work together, the internal security situation of the country can't be improved. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। इस बहस की शुरुआत जब अरूण शौरी जी ने की थी, तो मुझे उनकी बात से लगा कि वे कह रहे हैं कि सिचुएशन खराब है, लेकिन बद से बदतर नहीं हुई है, और उन्होंने एक ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): कृपया सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री राजीव शुक्ल: उन्होंने सीधे तौर पर सारी बातें रखी थीं कि क्या स्थिति है और हम भी उससे सहमत थे। लेकिन आज के एक राष्ट्रीय दैनिक में मैंने उनका लेख पढ़ा। ऐसा लग रहा है कि जब से यह सरकार आई है, छः महीने में, राष्ट्रीय सुरक्षा ध्वस्त हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे बिल्कुल आसमान गिर गया है। छः महीने में हो क्या गया है? मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि छः महीने में क्या हो गया है जो पिछले छः साल में नहीं हुआ था? इंडियन एक्सप्रेस में ...(**व्यवधान**)... मैं पिछले छः साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि छः साल वाले आरोप लगा रहे हैं। जैसे पता नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस हो रही है तो क्या हो गया है, यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या संसद पर हमला हो गया पिछले छः महीने में? पिछले छः साल के दरमियान हुआ था। क्या आई.सी. 814 का अपहरण हो गया-जो पहले हुआ था? क्या कोई कारगिल हो गया- जो पहले हुआ था? ...(**व्यवधान**)... जब होगा, तब देखेंगे। क्या हम कंधार में जाकर आतंकवादी सौंप आए? नहीं। क्या जानवरों की तरह बी.एस.एफ. के लोगों को लटकाकर बंगलादेश के बॉर्डर पर ले जाया गया? वहां के लोगों ने हमारे बी.एस.एफ. के लोगों को मारा था, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। आई.एस. आई. पिछले छः साल में जितनी बढ़ी, शायद कभी बढ़ी होगी, जब से आई.एस.आई. बनी है पाकिस्तान में, और व्हाइट पेपर लाने का वादा किया था पिछली सरकार ने, आज तक कोई व्हाइट

पेपर वे नहीं लाए। कश्मीर में रोज़ एक आर्मी कैंप पर हमला हुआ करता था, प्रो-एक्टिव पॉलिसी की बात होती थी कि हमारी प्रो-एक्टिव पॉलिसी होगी लेकिन उसके बाद? हॉट परस्यूट प्रो-एक्टिव लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती गईं। गुजरात में जो कुछ हुआ, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वरना शोर-गुल शुरू हो जाएगा। हमारे मित्र अरूण जेटली जी उधर बैठे हैं। इन सबको पता है कि पिछले छः महीने के अंदर ऐसा कोई गुजरात कांड भी नहीं हुआ, गोधरा-कांड भी नहीं हुआ, कोयम्बटूर का ब्लास्ट भी नहीं हुआ और किसी ग्राहम स्टेन्स को भी उड़ीसा में नहीं जलाया गया। तो क्या ऐसी बात हो गई, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी, कौन सा पहाड़ छः महीने में टूट गया कि सरकार बदलते ही लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई? सब बैठे हुए हैं, पूरा देश सत्यानाश हुआ जा रहा है, पता नहीं, क्या हुआ? यह क्या बात है मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

महोदया, पिछले छः महीने में जो कुछ हुआ है, वह अगर मैं आपको बतांऊ तो कश्मीर की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है, नॉर्थ-ईस्ट की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है और देश की जो सामान्यतः कानून और व्यवस्था की स्थिति है, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अगर मैं कश्मीर के कुछ आंकड़ों पर जाना चाहूं तो इनफिल्ट्रेशन में 50 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2003 में 1211 इनफिल्ट्रेशन के जो केसेज थे, वे 496 रह गए हैं। किलिंग्ज के 23 परसेंट इंसिडेंट्स कम हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की हत्या में 40 परसेंट की कमी आई है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): पांच महीने में?

श्री राजीव शुक्ल: छः महीने तो हमारे हुए न, मैं तुम्हारे वाले की बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: ये हमारे-तुम्हारे क्या हो रहा है?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री राजीव शुक्ल: अरे भाई, हमारे-तुम्हारे तो यही है। मैडम, आज कश्मीर में टेररिस्ट्स की जगह टूरिस्ट्स आ रहे हैं। किसी होटल में जगह नहीं है, एयरलाइन्स में सीटें नहीं मिल रही हैं, और यहां तक कि-मैं सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूं-हाउस-बोट्स पूरे भरे हुए हैं, वहां की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार हो रहा है। कश्मीर को अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, हत्याएं रुकने की दृष्टि से देखें, आर्म्ड फोर्सेज पर हमलों में कमी की दृष्टि से देखें तो काफी इंप्रूवमेंट है। लेकिन मैं यह कहता हूं, और फारूख साहब भी यहां बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ हरा-हरा हो गया है या मैं कोई रोजी पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से सुधार हुआ है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। कोई पहाड़ नहीं टूट गया है देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में।

मैडम, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर गए थे। वहां उन्होंने एक नया प्रयास शुरू किया कश्मीर के लोगों को जोड़ने के लिए। उन्होंने वहां पर मीटिंग्ज़ कीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): प्रधान मंत्री जी के जाने से पहले क्या हुआ था?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): प्रधान मंत्री जी के जाने से कितने घंटे पहले क्या हुआ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): बीच में व्यवधान मत डालिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल: भुवनेश्वर में क्या हुआ आप बताइए। वहां उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और मैडम जहां तक नॉर्थ-ईस्ट का प्रश्न है, वहां भी 27 प्रतिशत किलिंग्स में कमी आई है। नागालैंड में ...(**व्यवधान**)... नागालैंड के जो गुट थे या ग्रुप थे, उनकी भारत सरकार के साथ बातचीत हुई है, वहां भी सुधार हुआ है। तब कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो कश्मीर व नागालैंड, नार्थ-ईस्ट, दोनों जगह ज़बर्दस्त सुधार हुआ है। जहां तक नक्सलियों का प्रश्न है, प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो हथियार और हिंसा का त्याग करेंगे, वे उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छी और क्या नीति हो सकती है? इसका तो स्वागत करना चाहिए, जैसा कि फारुख अब्दुल्ला साहब ने अभी मेज़ थपथपा कर किया। इसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए कि हम सब लोगों को साथ में लाकर मुख्य धारा के साथ जोड़ कर चलना चाहते हैं और हिंसा में, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है, हिंसा में कमी आ रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एक वक्ता ने अभी उधर से कहा था, उस दिन मैं सुन रहा था कि इस सरकार को बहुत जल्दी है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोई जल्दी नहीं है। भारत देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करती है और कांग्रेस की यह नीति हमेशा से ही रही है। हम ऐसा नहीं करते कि एक तरफ कारगिल में लोग घुस जाएं और उधर से हम बस लेकर घुसें। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ...(**व्यवधान**)... हां वहीं, तब तैयारी चल रही थी, फारुख साहब, जब इधर हम घुस रहे थे उधर वे घुस रहे थे। तब वह तैयारी पहले से चल रही थी। यहां तक कि अभी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, उनका बयान तो आपने सुना ही होगा कि उन्होंने क्या कहा था कि हमको प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी ज्यादा सूट करते थे। तब अगर जल्दबाज़ी वाली बात है तो उनका बयान ही इस बात का उत्तर देता है कि पाकिस्तान को कौन ज्यादा सूट करता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ, हमारे विदेश मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हमारी यह नीति रहेगी कि उनके साथ हम दोस्ती रखेंगे। उनके साथ चाहे व्यापारिक संबंध हों, चाहे आर्थिक संबंध हों या फिर सामरिक संबंध हों, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मैं समझता हूं कि

इस देश की आंतरिक सुरक्षा में पिछले छ: महीनों में भारी सुधार हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कही से भी किसी आलोचना की गुंजाइश है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर इससे पहले कई माननीय सदस्यों ने बात की, उनमें जो दो प्रमुख बातें हैं, सारे सदन को, सभी वक्ताओं को एक चिंता जरूर है कि आंतरिक सुरक्षा मज़बूत हो, आंतरिक सुरक्षा का पहरा, जो राजद्रोही हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों पर कड़ा हो। जब बात इस छमाही के इम्तिहान की आती है, जैसा कि अभी राजीव जी कह रहे थे कि छमाही में हो क्या गया, इस सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि छमाही में सब कुछ बदल गया, तो डेफिनेटली अगर छमाही और छमाही के इम्तिहान की बात आएगी तो इस सरकार और इस सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर यदि सौ में से नम्बर देने होंगे तब पांच से ज्यादा नही मिल सकेंगे। इसलिए नहीं कि यह सरकार और इस सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के प्रति उतनी ही चिंता हो, उतना ही सरोकार हो, जितना पहले हमारी सरकार का था, लेकिन निश्चित तौर से नीतियों में स्पष्टता नहीं है। निश्चित तौर पर जो राजद्रोही लोग हैं, उनके प्रति किस प्रकार सख्ती से निपटा जाए, उसमें स्पष्टता नहीं है और आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल, उपसभाध्यक्ष जी, हमेशा स्पष्ट और राजनैतिक इच्छा शक्ति की मजबूती के साथ चलती है। अगर आप इस सरकार का छमाही का रिपोर्ट कार्ड देखें, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, इस छमाही में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि उन घटनाओं की कभी भी, किसी भी रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। कल ही जब गृहमंत्री जी लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर क्लीन चिट दे रहे थे और कह रहे थे कि घुसपैठ कम हुई है, आतंकवाद कम हुआ है, कमजोर हुआ है, तब उसी समय असम में आठ जगहों पर बम विस्फोट की घटनाएं हो रही थीं। जिस समय गृह मंत्री जी दूसरे सदन में कह रहे थे कि आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं, आतंकवाद कम हुआ है, आज मैं देख रहा था कि वे उसके आंकड़े भी दे रहे थे, उसी समय रिपोर्ट्स आ रही थीं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मीरपुर में, ब्रिटेन अपना दूतावास खोलने की बात कर रहा है। यह दोनों सदनों का एक संयुक्त प्रस्ताव है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न हिस्सा हैं। इसके बावजूद अगर वहां पर ब्रिटेन का स्थायी या अस्थायी दूतावास खुलने की बात हो रही हो और उसके बाद कहा जा रहा हो कि आतंकवाद कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, सीमा पार से आतंकवादी घटनाएं रुक रही हैं, कम हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि यह किसी भी रूप में, किसी भी तरह से इस सरकार और इस सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय हितों की नीतियों पर कई तरह से प्रश्न चिह्न लगाने वाली नीतियां रही हैं। पोटा और कई अन्य सवालों पर गृह मंत्री और कई अन्य वक्ताओं ने बात की। मुझे लगता है कि यह पोटा के मैरिट, डीमैरिट पर बहस का

4.00 P.M.

समय नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सुरक्षा बलों को जंग लगा हथियार देकर कहेंगे कि आप आतंकवादियों से लड़ो, अगर आप अपने सुरक्षा बलों को ऐसे हथियार, जो म्युजियम में रखने लायक हैं, उन्हें देकर कहेंगे कि आतंकवाद को खत्म करो, तो यह संभव नहीं होगा। जब मैं जंग लगा हथियार कह रहा हूं और म्यूजियम में रखने वाला हथियार कह रहा हूं तो मैं कोई गोली, बंदूक या तोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन कानूनों की, जो कानून आक्रामक ढंग से, मजबूती के साथ आतंकवाद को कुचल सकते हैं । वे कानून जो कहीं न कहीं घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उन कानूनों को खत्म करने की बात कर रहा हूं। लेकिन आतंकवाद को कुचलने की बजाय, कमजोर करने की बजाय, उन्हें डीमोरेलाइज करने की बजाय, यह सरकार आते ही घोषणा करती है कि पोटा हटा दिया जाएगा, पोटा से मानवाधिकार को नुकसान हो रहा है। पोटा हटाया जाता है, उसके बाद एक वैकल्पिक कानून लाया जाता है। आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट के बारे में पिछली एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने तमाम खामियों को देखने के बाद कहा कि आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट किसी तरह से घुसपैठ रोकने में सफल नहीं हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन यह सरकार आती है और कहती है कि नहीं, आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट बिल्कुल ठीक है, इससे घुसपैठ रुक रही है और झाड़-पोंछकर, ठीक करके आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट फिर से जिंदा किया जाता है। मेरा केवल इतना कहना है कि जब तक मतबूत राष्ट्रवादी, राजनैतिक इच्छाशक्ति सरकार में नहीं होगी, तब तक घुसपैठ और आतंकवाद को खत्म करना आसान काम नहीं होगा। घुसपैठ और आतंकवाद कोई ऐसा जिन्न नहीं है कि उसे पकड़कर बोतल में बंद कर दिया और घुसपैठ और आतंकवाद खत्म हो गया। आज छह महीने के इस सरकार के कार्यकाल में मैं यह नहीं कहता कि गृहमंत्री जी बहुत संवेदनशील या बहुत अनुभवी नहीं हैं, हो सकता है कि वे प्रयास भी कर रहे हों, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों में कहीं न कहीं कोई खामी है। उन प्रयासों में कहीं न कहीं कोई कमजोरी है, उन प्रयासों में कहीं न कहीं राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। अगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कम होने की बात हो रही है, तो मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं, हो सकता है कि यह आंकड़ों में कम हो रहा हो। जम्मू-कश्मीर में हर दूसरे दिन आतंकवादी घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं। जम्मू-कश्मीर में हर दूसरे दिन राजनैतिक लोगों पर हमले हो रहे हैं। जिस राजनैतिक प्रक्रिया के तहत जम्मू-कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने का काम पिछली सरकार ने किया था, जिन राजनैतिक हालातों को बेहतर बनाकर वहां के आम लोगों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल करने का काम पिछली सरकार ने शुरू किया था...। अगर उन राजनीतिक हालातों को ही बदतर बना दिया जाएगा, तो फिर इस बात की अपेक्षा करना, इस बात की उम्मीद करना कि जम्मू-कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं या वहां पर आतंकवादी खत्म हो रहे हैं या सीमा पार से आतंकवाद खत्म हो रहा है, मेरा मानना है कि यह ठीक नहीं है। डा॰ फारूक अब्दुल्ला साहब यहां बैठे हुए हैं, अभी पिछले दिनों ही खुद उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर हमले हुए, कई और राजनीतिक नेताओं पर हमले हुए। बात होती है कि बातचीत की जाएगी, तो बातचीत के प्रतिनिधि कौन होंगे? जब

राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो जो चुने हुए लोग हैं, वे भी बातचीत का हिस्सा होने चाहिएं लेकिन सरकार ने कभी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया। सरकार हमेशा कहती रही कि ''हुरियत'' से बातचीत होगी, अलगाववादियों से बातचीत होगी, इनसे बात होगी, उनसे बात होगी, लेकिन बातचीत किस दायरे में होगी और कौन लोग प्रमुख रूप से बातचीत का हिस्सा होंगे? वे लोग बातचीत का हिस्सा होंगे, जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, या वे लोग बातचीत का हिस्सा होंगे, जिन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया, राजनीतिक प्रक्रिया का बहिष्कार किया? क्या वे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं? वे लोग पाकिस्तान जाकर, पाकिस्तान की शर्तों पर हिंदुस्तान से बात करेंगे। अगर यह सीमा पर आतंकवाद को खत्म करने का तरीका है, तो मुझे लगता है कि यह तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि सीमा पार आतंकवाद को इससे और आक्सीजन मिलेगी।

महोदया, कुछ साथी कह रहे थे कि रोज़ी, रोटी, रोज़गार की कमी की वजह से आतंकवादी बढ़ गए हैं। कल गृह मंत्री जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं, जो लोग घुसपैठ करके आ रहे हैं, वे यहां पर रोज़ी-रोटी कमाते हैं और चले जाते हैं, इसलिए कई ऐसे लोग आ रहे हैं। मेरा मानना है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि रोज़ी, रोटी और बेरोज़गारी ने कभी भी आतंकवाद को जन्म नहीं दिया है, क्रांति को जन्म दिया है, इसके कारण क्रांति हो सकती है लेकिन आतंकवाद उसका justification नहीं है। अगर उसका justification कोई कहता है कि...

गृहमंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ तो कहा, मैंने वैसा नहीं कहा, इसलिए मुझे यह बताना पड़ेगा कि ये जो घुसपैठिए हैं, वे रोज़ी-रोटी के लिए आ रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: ऐसा आज अखबारों में आया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: अखबारों में तो आप जो बोलते हैं, वह आता है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): चलिए, मंत्री जी ने बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: मेरा यह मानना है कि रोज़ी, रोटी या गरीबी के कारण कभी भी आतंकवाद का जन्म हो, इसका justification न तो सरकार, न ही कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अभी किसी सदस्य ने भी यह बात कही थी।

अब जहां तक घुसपैठ का सवाल है, घुसपैठ एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक ऐसा ज़हर है, देश के लिए ऐसा खतरा है, जिसे आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। आज करोड़ों की संख्या

में हमारे यहां घुसपैठिए आ गए हैं, आज करोड़ों की संख्या में आए हुए ये घुसपैठिए, यहां की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं उसके बाद अगर यह कहा जाए, घुसपैठ को वोट की नज़रों से देखा जाए, घुसपैठ को किसी ऐसे रूप में देखा जाए, जिससे राजनीतिक फायदा और नुकसान का आकलन हो रहा हो, तो वह ठीक नहीं है। अगर इसको राष्ट्रीय हित के चश्मे से देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि घुसपैठ के मुद्दे पर न्याय किया जा सकता है। जब यह सरकार आई थी तो उसने 6 महीने के अंदर , बिना सिक्योरिटी एजेंसीज़ की रिपोर्ट को देखे हुए, बिना सिक्योरिटी एजेंसीज़ की चिंता को देखे हुए, POTA को खत्म कर दिया, बिना असम के लोगों की चिंता को देखे हुए, नार्थ-ईस्ट के लोगों की चिंता को देखे हुए, IMDT Act को झाड़-पोंछकर खड़ा कर दिया, यह मजबूत राजनीतिक और राष्ट्रवादी इच्छा-शक्ति का परिचायक नहीं है और मेरा मानना है कि ये ऐसी चीजें हैं, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को कहीं न कहीं चिंता में डाल रही हैं। सरकार ने घुसपैठ और आंतकवाद के मुद्दे पर कई बार ऐसी बातें इन 6 महीनों में कही हैं, सरकार के अलग-अलग मंत्रियों ने कही हैं। एक मंत्री कहते हैं कि घुसपैठ खत्म हो रही है, घुसपैठिए भाग रहे हैं, घुसपैठ में कमी आई है, उसी सरकार के दूसरे वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि नहीं, घुसपैठ खत्म नहीं हो रही है, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं.....

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: आप कृपा करके मुझे बोलने दीजिए। ये जो tactics हैं, अगर आप इन्हें न अपनाएं तो अच्छा रहेगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: (बिहार) माननीय गृह मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे , मैंने आप दानों का वक्तव्य सुना है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि उनमें जरूर कुछ अंतर है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: मुझे बोलने दीजिए। प्रणब मुखर्जी यहां पर बोल रहे थे, मैं यहां पर बैठ कर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सितम्बर में जो घुसपैठिए आए हैं, उससे ज्यादा अक्टूबर में आए। आप कहने जा रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई और होम मिनिस्ट बोल रहे हैं घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई। ये इस प्रकार से टैक्टिक्स करके हम लोगों में आप क्या झगड़ा लगाना चाहते हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: हमने आपकी सप्लीमेंटरी का उत्तर भी सुना और आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब की सप्लीमेंटरी का उत्तर भी सुना और हम लोगों की समझदारी बड़ी जिम्मेदारी से बनी कि आप दोनों में अन्तर है। ...(व्यवधान)

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सारी चीजें रेकार्ड में हैं और रेकार्ड की बात अगर हम लाना चाहें तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के माध्यम से भी ला सकते हैं। यह रेकार्ड में है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: रेकार्ड में यह भी है कि सदन और सदन के बाहर भी अलग-अलग

बयान दिए गए हैं। खास तौर से सदन के बाहर तो बयान दिए गए हैं अलग-अलग और कभी-कभी तो सदन चल रहा होता है...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): नकवी साहब, आपका समय खत्म हो रहा है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: और इस सरकार के मंत्री ज्यादा बयान देते हैं, आपके एमओएस सदन के बाहर ज्यादा बयान देते हैं तो इसलिए इस तरह के प्रिविलेज की भी बात होगी।

उपसभाध्यक्ष: आप कृपया समाप्त करें।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: सदन के बाहर बयान देना और सदन चल रहा है तो मुझे लगता है कि वे भी इस सीमा में आते हैं। मैं केवल इस बात को कह कर अपनी बात खत्म करूंगा कि आन्तरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति देश चिन्तित है। सभी राजनीतिक पार्टियों में बराबर की चिन्ता है। हम किसी रूप में इसे राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता या राजनीतिक द्वेष का हथियार बनाने के पक्षधर नहीं हैं। हो सकता है कि सरकार की नजर में राष्ट्रीय सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा राजनीतिक चश्मे से ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन हमारा केवल इतना अनुरोध है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, तो ऐसे मुद्दे पर सरकार, जैसा कि हमारे अहलुवालिया जी ने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, अगर उनके भी कुछ बेहतर सुझाव हैं, तो उनको देखें। ऐसा नहीं है कि आंख बन्द करके पोटा खत्म करना है तो बिना सुझाव के खत्म कर दिया, पोटा खत्म करना है तो सिक्युरिटी एजेंसी की बात को अनदेखा करके खत्म कर दिया। इसलिए सारे लोगों के सहयोग, सारे लोगों को विश्वास में लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा के मुद्दे पर देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की गरिमा, देश की अस्मिता, देश की मर्यादा को मजबूत रखने और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

उपसभाध्यक्ष: धन्यवाद। डा॰ पी॰ सी॰ अलेक्जेन्डर।

DR. P.C. ALEXANDER (MAHARASHTRA): Madam Vice-Chairman, I would like to begin with a few observations about our general attitude to internal security. As a nation, we have been attaching comparatively less importance to problems relevant to internal security than to external security. Somehow or the other, a philosophy seems to have developed among our people that once we have shaken off the foreign yoke and asserted our right to be our own masters in our own houses, sovereignty will automatically be preserved, security will automatically be part of the element of sovereignty; and, therefore, we are treating internal security as if it is only a law and order problem. Confusing law and order with internal security has been the greatest weakness in our approach to internal security problems. That is my first point.

We are forgetting the lesson of post-World War-II history. If we analyse what has happend to various nations in the post-world War period, we should really be much more concerned on the problem of internal security than what we are today.

What happened to the Soviet Union? What happened to Yugoslavia? What has happened to the numerous States in African continent? States have disappeared. States have got disintegrated, States have failed, new States have emerged and the reason has not been an attack from outside, in most of these cases, In 90 per cent of the cases, where States have failed or fallen or got disintegrated, the real reason has been failure to maintain internal security. That lesson we have not yet understood properly. The second point I want to raise about internal security follows from the first. At the Central level, we think it is only the responsibility of the Home Ministry. At the State level, they think it is the responsibility only of the Home Department. Internal security, Madam, Vice-Chairperson, is not merely a matter for the Home Ministry or the Home Minister. The Education Ministry for example, in my opinion, has an equal reponsibility to ensure internal security because it is only by educating the youth of the country, the young children of the country, on the spirit of true patriotism, on the paramount need of love of one's own country, on the importance of national integration, that we can maintain security. If we know the history of the united States in the early stages of its formation and how will they used schools and syllabi to promote national integration and to build up one nation out of a multitude of the nationals of the world who had chosen to be emigrants to that country, we can learn a lesson from that. But we do not consider education as a tool for national integration or and for maintaining internal security. I do not agree with the comments made either by General Shankar Roy Choudhry or by Shri Ashwani Kumar that this is a matter for the State Governments and therefore we should interfere with the least. I will come to that when I deal with Naxalite problem which is the main subject of my talk today. I am not going to discuss other issues, in the North-East, the religion-based separatist movement in Kashmir or the, narcotism-inspired terrorism in some parts of our country. But I want to bring to the attention of the hon. Home Minister and the Members of the House to my firm conviction that our security is in serious danger because of rise of Naxal movement in the last four-five years. It has been there for the last forty-five years. I know that. But in the last four-five

years, it has really developed into a danger point and if we fail to take note of the danger that we see in the Naxalite movement, I am afraid the consequences would be fatal. I use that word 'fatal' with all sense of responsibility to our future as an integrated nation. Till now, we were mainly concerned about Naxalite movements in Andhra Pradesh; in Bihar; after the separation of Jharkhand, in Jharkhand. But very soon in the last few years particularly, the Naxalite movement has spread its tentacles from Andhra Pradesh, Bihar and Jharkhand to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharastra, West Bengal, Orissa and Chhattisgarh. Nine States are now in the grip of Naxalite movement in our country and there is every trend that I see today of the movement spreading towards Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Uttaranchal. Thirteen States are in serious danger of the Naxal movement, overpowering their States strength and becoming a real danger to existence as an integrated country. 157 out of 593 districts in our country have already been affected in some form or the other. Madam, Vice-Chairperson, I find three recent developments as extremely dangerous. Please don't think that I am exaggerating. I am old enough to be careful about my words and about the language I use to express my sentiments. But with full sense of responsibility I would like to remind the hon. Minister and the hon. Members of the House that we have to take serious note of these three developments.

The first has been the merger of CPI (ML)-PWG and MCC (I) in September, 2004. After the merger of these two groups, the newly found Maoist party has control over 92 per cent of all naxal activities all over the sub-continent of India. That is a very dangerous development we can now say that one party is in full control of the entire naxalite movement in this country.

The second development, has been the sudden triumph or success of the Maoist movement of Nepal in that country. I have already, through a supplementary question in the other day mentioned this fact. But, we have to understand the repercussions of what is happening in our neighbouring State and on our own country, because we cannot wish away our neighbour and by indulging in the niceties of international relationship, we should not igore what is of vital concern to our own country. And, therefore, I wish to do a little plain- speaking about the developments in Nepal.

[MR. CHAIRMAN in the Chair]

Sir, 68 districts out of 75 in Nepal today are in the grip of the naxalites. The real fact is, as has been mentioned in articles-after-articles; by some european Journals the police have withdrawn from rural areas and are concentrating only in the urban areas. In a general way, one can say, the Maoists, today, rule the rural countryside of Nepal, and the Government of that country has control only over the capital city and the urban areas. Where does the danger come out of this? Because, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and many other States in our country, have to take serious note of what happens in Nepal. We just cannot say that there is a geographical boundary between one nation and another. What has happened during the last five years in Nepal will have very serious repercussions on our country if we do not give weight to that. Particulary I mention this danger particularly because some of the districts bordering Nepal are really vulnerable to law and order collapse. According to the intelligence reports gathered by sources even from outside our country, the Naxalite Movement in Nepal is slowly moving towards the borders of India. Having achieved what they wanted in Nepal's rural areas, now, they are now turning their attention towards our own boundaries. That is how the concept of revolutionary zone, starting from Nepal, Bihar, covering Jharkhand, certain areas of Dandakaranya, going right down to Andhra Pradesh to other southern States. It is the grand design of the party. Let us not forget this. Full intelligence must e available on what I am talking with our intelligence department and RAW. There has always been a very close interaction between the Naxalite parties in India and the naxal parties in Nepal, not merely on ideological terms or for training of people, but even in exchange of weapons. Now, that there is one united naxal party here, the danger is greater. The third point that I wish to make is with regard to the State of Bihar. I hope my friends from Bihar will not misunderstand me. I have great respect for the people of Bihar. In my younger days the best civil servants of the country came from Bihar. And, we considered them as role models. But today, unfortunately, I am compelled to say that that State which is to take the heaviest load or pressure from across the border is not so dependable a barrier for India, as it should have been or as it should be. Therefore, the State Government of Bihar has to be considerably strengthened in order to fight the menance of Maoism from Nepal.

Sir, I was not at all happy with some parts of the report that the

Ministry of Home Affairs has circulated this morning. I feel particularly unhappy at one paragraph, referring to the peace, talks in Andhra Pradesh. And, I hope, the Home Minister will understand my sentiments when I say it. Referring to the peace talks in Andhra Pradesh, the report of the Home Ministry says, as the conclusion of the meeting of Chief Ministers held in Andhra Pradesh, "If, in its assessment, a State finds the conditions conducive, it may hold peace talks with the Naxal groups in any manner it decides to do so." The State Government can hold peace talks if it decides it is necessary. It can do so in any manner as it thinks to do so! And, then, it says "The purpose of the talks should be to strengthen peace, tranquillity and reduce reliance of Naxal groups on armed struggle." I am really nervous. I hope it is a bad drafting that has excelled in this piece of reporting. How can you say that the Home Ministry is willing to give this freedom to have talks with the naxalities at the time of its choice, at the manner of its liking? How can you say? Secondly, how can you say in the next sentence, as a sort of explanation, that the purpose of the talks should be to reduce the reliance of Naxal groups on armed struggle? Are we here only to reduce that? Or, are we here, in the Home Ministry, or, in this great Parliament to totally eliminate their dependence on armed struggle? Do you condone armed struggle by the Naxalities, whatever may be their ideological pretensions? I say, Can the Government, under any circumstances, say, in a report like this, that our objective is to reduce their dependence? That means they can still have arms. I am sure this is a mistake.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Will you please yield for a moment? Let us understand that this is a gradual process. You are saying that the reliance on the armed struggle by the Naxalites should be ended.

DR. P.C. ALEXANDER: That should be your objective, not reducing the reliance.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That is the objective. 'Reducing' means you are going gradually. You are talking to them. And, in the first talk you want to see that it is ended. *(Interruptions)*

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, I Cannot forget my past. As an old administrator, I would like to advise my young colleagues in the Home Ministry that when you draft, you should put the objective in clear and unambiguous terms; and, don't use words like, "We are going gradually."

They will gradually kill us all. Nobody will be left to talk to them *(Interruptions)* You may reply to me later. *(Interruptions)*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: No; no, please. This is a very important point. You are concentrating on your point of view. We are hearing very carefully every word that you are saying. And, we are going to act on your advice. You just rely upon that. But let us not interpret the things in such a manner that gives a wrong impression in the country.

DR. P.C. ALEXANDER: No, I will come to that point also. If you allow a State Government ... *(Interruptions)*.. I am now speaking here on the last point of my speech, and you have led me to speak on it now. If you allow the State Government of Andhra pradesh to decide to whom to talk, how to talk, what to talk, when to talk, in any manner as if it is entirely a State subject, I would like to enter very strong reservations on that. You, as the Home Minister, are responsible for the internal security of the entire nation of one billion and 20 million people. And we cannot leave internal security as a matter for the Government of Andhra Pradesh to tackle. What is happening in Andhra Pradesh is affecting all of us. It will affect the people in the whole country. And it is in our interest, the interest of the whole country that you should have a decisive voice as to when, what, how they should talk. You, as the home Minister, should not abdicate; this responsibility and to ... *(Interruptions)*....

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Then, what did we go there for, if we had not to discuss with the Home Ministry? ...*(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: I thought you went there to ensure ... *(Interruptions)* But, probably, it is ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We did hold the meeting. We were discussing it. And it is not necessary that all ;that we had discussed in that meeting should be disclosed here. ...*(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: Unfortunately, when you went there, I don't know what happened between you and the three Chief Ministers of four Chief ministers out of nine who attended that, except from what you have reported in your official statement. I am reading out your report. That is why I say ...*(Interruptions)*... I give you the benefit. ...*(Interruptions)*... It may be poor drafting. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will give the reply when I speak. ...*(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: The objective should be clear. If you say that slowly we will reach that obejctive, certainly, it is welcome. I would earnestly plead with you that you should take charge of the issue of internal security and continue to be in full charge and not leave it entirely .... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him finish. ... *(Interruptions)*..

DR. P.C. ALEXANDER: ...to one Government because the simple philosophy is this. If Naxalite movement fails... ... *(Interruptions)*... Its failure in Andhra Pradesh would mean success of the whole Country and the Home Ministry here. Its success in Andhra Pradesh would be having the reverse effect for the whole country. I am not finding fault with you, Mr. Home Minister. I have great respect for you and regard for the high standards of intelligence which you have as a leader. I have great respect for the civil servants working with you. Maybe, it is a drafting blunder. But it sends a wrong message. People will get the impression that you are willing to talk. I will just add one dimension to it.

I now talk as a representative from Maharashtra. The naxals in Two of the districts in Maharashtra, Gadchiroli and Gondia, are just following what their political; masters in the Naxalite movement tell them to do from across the border. They have no local leaders; they just carry out instructions. When the Naxalites are sitting round the table with the Cheif Minister and the senior officers of the Government, in Hyderabad; they are shooting out people in Gondia and in Gadchiroli. They are the same people; udner the same leadership. Therefore, it is not entirely peace talk in Andhra Pradesh. It is not entirely a matter for Andhra Pradesh. It is very much a matter for its neighbouring States and for the whole country. If I have created an impression that I am finding fault with you, Mr. Home Minister, you will be ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am very happy that you are raising it. ... *(Interruptions)*...

DR. P.C. ALEXANDER: I am speaking out because I strongly feel that unless we not only speak out, but also act strongly and convey the

message to the Naxalites that "I am going to be in charge of this movement to suppress you activities in this country, I will maintain the integrity and oneness of our nation with all my might," we may end up in a disaster. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sanjay Nirupam.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH): Mr. Chairman, Sir, I want to say a word. ... *(Interruptions)* ... My distinguished colleague ... *(Interruptions)*...

SHRI BIMAL JALAN (Nominated): Mr. Chairman, Sir, can I seek a clarificaiton from Dr. P.C. Alexander? ... *(Interruptions)* ... I am thankful for his very powerful speech with which all of us ...*(Interruptions)*... across the House, across the different divisions would agree. ... *(Interruptions)*... Sir, internal security is a most important matter. Sir, my clarification is ... *(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: No. ... *(Interruptions)*...

श्री संजय निरुपम: सर, नहीं नहीं , ऐसे थोड़े ही होता है। ....**(व्यवधान)** जब उनकी बारी आएगी, सभापति जी आज्ञा देंगे, तब बोलना चाहिए। ....**(व्यवधान)** ऐसे थोड़े ही होता है। ....**(व्यवधान)**

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): बोलने दीजिए ना। ....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: लीडर आफ द अपोज़ीशन क्या कह रहे है।? ....**(व्यवधान)** आप बोलिए। ....**(व्यवधान)**

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): May I plead on behalf of the hon. member, if you yield for a minute, Sir? Sir, I am indeed very very happy and grateful to the Members, especially, the senior Members. They have made excellent points and we are going to remember everything they have said. But, at the same time, if there is some exchange of views by seeking some clarfications, it should be encouraged rather than discouraged and the rule provides that a Member can seek explanation from another Member also ... *(Interruptions)*...

SHRI SANJAY NIRUPAM: There is no such rule... *(Interruptions)*..

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, आपने एलाउ किया है। .....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: आप बैठिए-बैठिए, अभी मैं एलाउ नहीं करुंगा। ....**(व्यवधान)** आप बोलिए।